Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 10
अंक : 255
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.00
रविवार, 21 सितम्बर, 2025

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

3 कानून-व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन से ...

4 क्या 22 सितंबर से आसान हो जाएगी ....

7 दुबई में पाकिस्तान से 'महाजंग', सूर्यकुमार ...

संक्षिप्त न्यूज

दिल्ली के 100 से अधिक स्कूलों को बम की धमकी, जांच में फर्जी पाई गईं

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के 100 से अधिक स्कूलों को शनिवार सुबह बम की धमकी मिली जो बाद में तलाश अभियान में फर्जी पाई गईं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि शनिवार सुबह 6.10 बजे ईमेल'टेरराइज़र्स111' समूह के नाम से आया था। इस समूह ने पहले भी स्कूलों को इसी तरह के ईमेल भेजे थे। ई-मेल का विषय था "आपके भवन में बम रखे गए हैं-कदम

उठाएं या आपदा का सामना करें।" दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें द्वारका स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस), कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल, सर्वोदय विद्यालय, द्वारका स्थित सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल और नजफगढ़ स्थित माता विद्या देवी पब्लिक स्कूल समेत 10 स्कूलों के बारे में सूचना मिली थी। हालांकि, परिसर की गहन जांच के बाद धमकी फर्जी पाई गई। उन्होंने बताया कि धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद बम निरोधक दस्ते और पुलिस दल परिसरों में पहुंचे और एहतियात के तौर पर छात्रों व कर्मचारियों को परिसर से बाहर निकाला। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, " हमने परिसरों की गहन जांच की हैं। अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है।" पुलिस ने बताया कि अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि धमकियां किसने दीं और यह भी पता लगा रहे हैं कि क्या ये धमकियां दहशत फैलाने के किसी समन्वित प्रयास का हिस्सा हैं।

मोदी का कांग्रेस पर तीखा वारः

6 दशक तक विदेशी निर्भरता में उलझाया, घोटालों से रोका देश का विकास

भावनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी ने भारत की क्षमता को नज़रअंदाज़ किया। गुजरात के भावनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने 1991 से पहले के लाइसेंस-कोटा राज और भारत के बाज़ार खोलने के बाद आयात पर कांग्रेस के ज़ोर की आलोचना की। आत्मनिर्भरता के अपने आह्वान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा और दुनिया के सामने मज़बूती से खड़ा होना होगा। भारत में क्षमता की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज़ादी के बाद कांग्रेस ने भारत की पूरी क्षमता को नज़रअंदाज़ कर दिया।

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इसलिए आज़ादी के 6-7 दशक बाद भी भारत को वह सफलता नहीं मिली जिसका वह हक़दार था। इसके दो बड़े कारण थे। लंबे समय तक कांग्रेस सरकार ने देश को लाइसेंस-कोटा राज में उलझाए

रखा और उसे विश्व बाज़ार से अलग-थलग रखा। और फिर, जब वैश्वीकरण का दौर आया, तो आयात का ही एकमात्र रास्ता अपनाया गया। उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान हुए घोटालों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि उनकी नीतियों ने भारत की असली ताकत को उजागर होने से रोका।

पीएम मोदी ने कहा कि हज़ारों, लाखों और करोड़ों के घोटाले हुए। कांग्रेस सरकारों की नीतियों ने देश के युवाओं को बहुत नुकसान पहुँचाया। इन नीतियों ने भारत की असली ताकत को उजागर होने से रोका। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि देश का 'सबसे बड़ा दुश्मन' दूसरे देशों पर निर्भरता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत 'विश्वबंधु' की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। दुनिया में कोई हमारा बड़ा दुश्मन नहीं है। अगर हमारा कोई दुश्मन है, तो वह है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन, निर्भरता के दुश्मन को हराना होगा। हमें इसे हमेशा दोहराना चाहिए।

उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थिर और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए भारत बड़ी विदेशी निर्भरता बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि विदेशी निर्भरता जितनी अधिक होगी, देश की विफलता उतनी ही बड़ी होगी। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना होगा। अगर हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे, तो हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। हम 1.4 अरब देशवासियों का भविष्य दूसरों पर नहीं छोड़ सकते। हम देश के विकास के संकल्प को दूसरों पर निर्भर नहीं छोड़ सकते। हम आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते।

निर्वाचन आयोग 'वोट चोरी' के बारे में कर्नाटक सरकार की सीआईडी को जानकारी नहीं दे रहाः राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया कि वह राज्य में कथित 'वोट चोरी' के संबंध में कर्नाटक सरकार की सीआईडी द्वारा मांगी गई जानकारी को उपलब्ध नहीं करा रहा है।

अपनी मां सोनिया गांधी के साथ शुक्रवार को वायनाड पहुंचे राहुल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि कर्नाटक सरकार के 'अपराध अन्वेषण विभाग' (सीआईडी) ने 'वोट चोरी' में इस्तेमाल किए गए नंबरों के बारे में जानकारी मांगने के लिए निर्वाचन आयोग को कई पत्र भेजे हैं, लेकिन आयोग इसे उपलब्ध नहीं करा रहा है।

कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) हैं और वह पुलिस द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा, "सीईसी पर इससे बड़ा कोई अभियोग नहीं हो सकता। पुलिस जानकारी मांग रही है, और वह जानकारी नहीं दे रहे हैं। यह मेरा बयान नहीं है। यह एक तथ्य है। यह स्पष्ट रूप से मौजूद है।" राहुल ने कहा कि कांग्रेस कथित 'वोट चोरी' के सबूत ऐसे तरीके से दिखाएगी कि किसी को भी इस बात पर कोई शक नहीं रह जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऐसा किया और चुनाव जीता।

उन्होंने कहा, "जैसा कि मैंने अपने दो संवाददाता सम्मेलन में कहा है, हम एक 'हाइड्रोजन बम' का खुलासा करने जा रहे हैं, जो वास्तविकता की मौजूदा स्थिति को पूरी तरह से तहस-नहस कर देगा।

हम जो कह रहे हैं उसके हमारे पास स्पष्ट सबूत हैं।" उन्होंने कहा, "हम बिना सबूत के कुछ नहीं कह रहे हैं। मैं अपना काम करूंगा और उसे पूरा करूंगा।" राहुल ने शुक्रवार को भी 'वोट चोरी' के आरोपों को दोहराया था और निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए उसे ऐसा "चुनावी चौकीदार' बताया था जो 'जागता रहा, चोरी देखता रहा और चोरों को संरक्षण देता रहा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के गयाजी स्थित विष्णुपद मंदिर में पिंड दान किया

गया।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए बिहार के गयाजी स्थित विष्णुपद मंदिर में पिंड दान किया। विष्णुपद मंदिर ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष शंभू लाल विट्ठल ने बताया कि राष्ट्रपति ने पूजा स्थल पर पिंडदान और जल तर्पण किया।

पत्रकारों से बात करते हुए विट्ठल ने कहा, राष्ट्रपति ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए फल्गु नदी के तट पर और विष्णुपद मंदिर में पिंड दान और जल तर्पण किया।

ऐसा माना जाता है कि पिंड दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। हर साल पितृ पक्ष के दौरान बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालु अनुष्ठान करने के लिए विष्णुपद मंदिर आते हैं।

इससे पहले गयाजी हवाई अड्डे पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और राज्य मंत्री प्रेम कुमार ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति की गयाजी यात्रा के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे।

एनएसए डोभाल की कनाडाई समकक्ष के साथ बैठक, सुरक्षा सहयोग समेत इन मुद्दों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली।राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में 18 दिसंबर को अपनी कनाडाई समकक्ष नतालि जी. ड्रूइन से मुलाकात की। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच नियमित द्विपक्षीय सुरक्षा संवाद का हिस्सा थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कनाडा के समकक्ष मार्क कार्नी के बीच कनाडा के अल्बर्टा में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई चर्चा को आगे बढ़ाने का भी अवसर था। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने एक आधिकारिक बयान में शनिवार को यह जानकारी दी गई।

दोनों पक्षों के बीच इन मुद्दों पर हुई चर्चा

दोनों पक्षों ने माना कि राजनीतिक नेतृत्व के बीच उच्चतम स्तरपर फिर से भरोसे को बनाने और सहयोग को बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी गतिविधियों, अंतरराष्ट्रीय संगठिन अपराधों से लड़ने और खुफिया जानकारी साझा करने जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों ने सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और मौजूदा संपर्क तंत्रों को और मजबूत करने पर सहमति जताई।

क्षेत्रीय व वैश्विक घटनाक्रमों पर साझा किए विचार

दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने भविष्य के सहयोग के क्षेत्रों पर भी विचार-विमर्श किया और क्षेत्रीय व वैश्विक घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के नए अध्याय के लिए करीबी सहयोग करने और सहयोग का दृष्टिकोण अपनाने पर सहमति जताई।

दिल्ली में आयोजित किया गया विदेश कार्यालय परामर्श

इन चर्चाओं के आधार पर भारत और कनाडा ने 19 सितंबर को नई दिल्ली में विदेश कार्यालय परामर्श (एओसी) आयोजित किया, जिसकी अगुवाई सचिव (पूर्व) पी. कुमारन ने की, जबकि कनाडाई पक्ष का नेतृत्व उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने किया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, ये परामर्श प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी के 17 जून 2025 को कनाडा के कनेनास्किस में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद हुए।

इन चर्चाओं ने भारत-कनाडा द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा करने और अन्य अंतरराष्ट्रीय व क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान किया। दोनों पक्षों ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन के सम्मान और संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित भारत-कनाडा संबंधों के महत्व की पुष्टि की।

टीवीके प्रमुख विजय बोले- मछुआरों की समस्या का समाधान निकालना हमारा प्रमुख एजेंडा

नागपट्टिनम (तमिलनाडु)। तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) पार्टी के प्रमुख विजय ने शनिवार को सत्तारूढ़ द्रमुक सरकार पर तीखा हमला किया और कहा कि मछुआरों की समस्याओं का समाधान ढूंढना उनकी पार्टी के सबसे अहम एजेंडों में शामिल है। विजय ने बताया कि तमिलनाडु में मछली निर्यात के मामले में नागपट्टिनम बंदरगाह दूसरा सबसे बड़ा है, लेकिन यहां आधुनिक सुविधाएं और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस जिले में आज भी कई परिवार झोपड़ियों में रहते हैं, जो यहां की कमजोर बुनियादी ढांचे की स्थिति को दिखाता है।

हमारे लिए महत्वपूर्ण मछुआरों और ईलम तमिलों का जीवनः विजय

उन्होंने कहा, हम द्रमुक की तरह नहीं हैं जो मछुआरों के मुद्दे पर लंबा पत्र लिखते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। मछुआरों की समस्या का समाधान निकालना हमारा प्रमुख एजेंडा है। विजय ने यह भी कहा कि मछुआरों का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ईलम तमिलों के सपने और जीवन भी उतने ही जरूरी हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 14 साल पहले उन्होंने नागपट्टिनम में मछुआरों पर हमलों के खिलाफ जनसभा की थी, जिससे

यह स्पष्ट होता है कि वह इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से प्रतिबद्ध हैं।

अपने संबोधन में विजय ने दुनियाभर के ईलम तमिलों के प्रति एकजुटता भी जताई। उन्होंने कहा, चाहे वे श्रीलंका में हों या दुनिया के किसी और हिस्से में, हमारे ईलम तमिल आज भी पीड़ा में हैं क्योंकि वे एक ऐसे नेता (लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन) को खो चुके हैं, जिन्होंने उन्हें मां जैसा स्नेह दिया था। हमारा कर्तव्य है कि हम उनके लिए आवाज उठाएं।

विजय ने त्रिची से शुरू किया राज्यव्यापी अभियान

13 सितंबर को विजय ने त्रिची से अपने राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत की थी। उस दौरान भी उन्होंने द्रमुक सरकार पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाया था। विजय ने कहा कि द्रमुक ने 2021 के चुनावी घोषणा पत्र में कई वादे किए, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा, एक अस्पताल में किडनी चोरी हुई। यह अस्पताल एक द्रमुक नेता का है। महिलाओं को भले ही मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिली है, लेकिन 'फ्री, फ्री' कहकर उन्हें नीचा दिखाया जा रहा है।

'समझौता किए बिना काम करेगी टीवीके'

उन्होंने कहा कि टीवीके पार्टी शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और न्यायिक सुधार जैसे मुद्दों पर बिना समझौता किए काम करेगी।

अदालती आदेशों के खिलाफ अपील की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की जरूरतः मेघवाल

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शनिवार को कहा कि सरकारी विभागों में अदालती आदेशों को चुनौती देने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की जरूरत है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) के एक सम्मेलन को यहां संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कई बार अदालतों द्वारा ठोस फैसले दिए जाने के बावजूद सरकारी विभाग अपील दायर कर देते हैं।

उन्होंने संकेत दिया कि कभी-कभी अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए अदालत या कैट के आदेशों को चुनौती देने के लिए अपील दायर करते हैं, क्योंकि फैसलों में उनके द्वारा लिए गए निर्णयों पर सवाल उठाए गए होते हैं। मेघवाल ने कहा कि उन्हें नियमित रूप से ऐसी फाइलें मिलती रहती हैं, जिनमें केंद्रीय विभाग ठोस अदालती आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने की योजना बना रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि सीएटी (कैट) को ई-फाइलिंग और डिजिटल सुनवाई जैसी नवीनतम तकनीकों का उपयोग करना होगा।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने 574 करोड़ रुपये के इक्विनिक्स डेटा सेंटर का उद्घाटन किया

चेन्नई।तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एसआईपीसीओटी-सिरुसेरी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पार्क में 574 करोड़ रुपये की लागत से विकसित इक्विनिक्स डेटा सेंटर का शुक्रवार को उद्घाटन किया, जिसका मकसद राज्य को भारत के डिजिटल केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

'इक्विनिक्स' ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के लिए अनुकूल बुनियादी ढांचा मुहैया कराने के वास्ते तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के सिरुसेरी में एक अत्याधुनिक डेटा सेंटर का निर्माण किया है।

'इक्विनिक्स' एक अग्रणी डिजिटल अवसंरचना प्रदाता कंपनी है, जो वैश्विक व्यवसायों को अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी समाधान प्रदान करती है और दुनिया के कई देशों में डेटा सेंटर संचालित करती है। इसका मुख्यालय अमेरिका में है।

मुख्यमंत्री स्टालिन की मौजूदगी में सआईपीसीओटी-सिरुसेरी आईटी पार्क में डेटा सेंटर की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

थे। स्टालिन ने जुलाई 2022 में निवेशकों के शिखर सम्मेलन के दौरान परियोजना की आधारशिला रखी थी।

उन्होंने सचिवालय में उद्योग विभाग की ओर से आयोजित एक समारोह में इस डेटा सेंटर का उद्घाटन किया। राज्य सरकार ने एक बयान में कहा, 'तमिलनाडु सरकार जरूरी निवेश आकर्षित करने, युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार सृजित करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को 10 खरब अमेरिकी डॉलर के स्तर तक ले जाने के लिए कई विशेष पहल कर रही है।'

बयान में कहा गया है कि हाई-टेक परियोजनाओं को आकर्षित करने और इस तरह बड़े पैमाने पर उच्च-वेतन वाली नौकरियां पैदा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें कहा गया है, 'चूंकि, चेन्नई सूचना और डेटा केंद्रों के एक प्रमुख केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है, इसलिए यह उल्लेखनीय है कि विभिन्न कंपनियां नये डेटा सेंटर स्थापित कर रही हैं।'

उद्घाटन कार्यक्रम में उद्योग मंत्री टीआरबी राजा, मुख्य सचिव एन मुरुगनंथम, उद्योग विभाग के सचिव वी अरुण रॉय, इक्विनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मनोज पॉल और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

आत्मनिर्भर भारत से ही पूरा होगा जगद्गुरू बनने का सपनाः मोहन मांझी

भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री मोहनचरण मांझी का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत ही स्वदेशी के संकल्प और भारत के जगद्गुरू बनने का सपना पूरा करेगा। वे यहां उड़िया दैनिक 'निर्भय' के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि की आसंदी से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा विकसित भारत हमारा साझा सपना है, सभी अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो इसे कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने कहा कि भारतीय भाषाएं बचेंगी तभी भारत बचेगा। उनका कहना था किसी भी देश ने पराई भाषा में न तो प्रगति की है, न ही मौलिक विचार इससे उपजते हैं। इसलिए भारतीय भाषाओं के उत्थान से ही हमारी कला, साहित्य, संस्कृति, सिनेमा,रंगमंच और प्रदर्शन कलाएं संरक्षित रहेंगी। उन्होंने कहा कि स्वराज लाना है तो 'स्वदेश' बनाना भी होगा, तभी स्वदेशी के आधार पर देश खड़ा होगा।

प्रोफेसर द्विवेदी ने कहा कि हमने वसुधा को कुटुम्ब माना पर आज तो हमारे परिवार भी खतरे में हैं। परिवार नहीं बचे तो मूल्य और संस्कृति दोनों नहीं बचेगी।

कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार सत्य सुंदर बारीक, संपादक नवीन दास ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष जय नारायण मिश्र, पूर्व वित्त मंत्री प्रफुल्ल घड़ेई, पूर्व कृषि मंत्री अमर प्रसाद सत्पथी, उड़िया फिल्म अभिनेत्री पिंकी प्रधान, साहित्यकार गौरहरि दास, भाजपा प्रवक्ता सज्जन शर्मा उपस्थित रहे। संचालन संबित महापात्र ने किया।

तमिलनाडु चुनावों पर नज़र, बीजेपी ने बनाया एनडीए का कुनबा बढ़ाने का प्लान?

चेन्नई। तमिलनाडु की विशिष्ट चुनावी गतिशीलता को देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में नए दलों को शामिल करने की तैयारी कर रही है। पार्टी ने मिशन मोड रणनीति अपनाई है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आगामी चुनाव में डीएमके विरोधी वोट बंटे नहीं। मतदाताओं के हर वर्ग पर नज़र रखते हुए, भाजपा ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की पुष्टि के अनुसार, इसका ध्यान वोटों के बंटवारे को रोकने पर है, जिससे सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) को फ़ायदा हो सकता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, भाजपा छोटी पार्टियों को एनडीए के दायरे में लाने पर काम कर रही है।

प्रमुख गठबंधन सहयोगियों के बीच चर्चाएँ शुरू हो चुकी हैं। इस हफ़्ते की शुरुआत में, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) के नेता ई. पलानीस्वामी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और चुनावी रणनीति और

एआईएडीएमके से पहले निष्कासित नेताओं की संभावित वापसी पर विचार-विमर्श किया। हालांकि, अन्नाद्रमुक सूत्रों के अनुसार, ईपीएस ने अमित शाह से कहा कि भाजपा को अन्नाद्रमुक से निष्कासित नेताओं को पार्टी में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे गठबंधन की एकता प्रभावित हो सकती है। इसके बावजूद, दोनों दलों ने सत्तारूढ़ द्रमुक सरकार से जुड़े जन मुद्दों के समाधान के लिए अगले महीने से एक संयुक्त अभियान शुरू करने पर सहमति जताई है। पूर्व नेताओं को फिर से शामिल करने का मामला अभी भी अनसुलझा है। पूर्व उपमुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम (ओपीएस) के बारे में सूत्रों का कहना है कि भाजपा उन्हें अपने पाले में लाने के लिए इच्छुक है। खबरों के मुताबिक, ओपीएस दिसंबर के अंत या जनवरी में भाजपा में शामिल हो सकते हैं, जिसका अन्नाद्रमुक स्वागत नहीं कर सकती। तमिल सुपरस्टार विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) को एनडीए में शामिल करने पर भी बहस चल रही है। एआईएडीएमके का मानना है कि पिल्लई जाति से आने वाले विजय, अगाड़ी जाति के वोट ला सकते हैं। हालाँकि, भाजपा अभी इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि उसका मानना है कि विजय केवल डीएमके के वोटों में सेंध लगाते हैं।

राजस्थान में दिखा भारतीय सेना का शक्ति प्रदर्शन, किया गया 'अमोघ फ्यूरी' युद्धाभ्यास

जयपुर।भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान ने हाल ही में राजस्थान के थार रेगिस्तान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक प्रमुख एकीकृत अग्नि अभ्यास, जिसका कोडनाम 'अमोघ फ्यूरी' था, आयोजित किया। इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक समय के युद्ध परिदृश्यों में युद्ध शक्ति, समन्वय और परिचालन तत्परता का परीक्षण करना था, जो बहु-क्षेत्रीय अभियानों के लिए सेना की तैयारी को दर्शाता है। इस अभ्यास में युद्धक टैंकों, पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों, हमलावर हेलीकॉप्टरों, लंबी दूरी की तोपों और ड्रोनों का समन्वित प्रदर्शन किया गया। इन प्लेटफार्मों को एक साथ तैनात किया गया ताकि प्रभावी आक्रामक और रक्षात्मक कार्रवाइयों के लिए जमीनी और हवाई साधनों को समन्वित करने की सेना की क्षमता का प्रदर्शन किया जा सके।

'अमोघ फ्यूरी' का मुख्य फोकस आधुनिक तकनीकों का एकीकरण था, जिसमें नेटवर्क-केंद्रित संचार, कमांड-एंड-कंट्रोल आर्किटेक्चर, और रीयल-टाइम निगरानी एवं लक्ष्यीकरण प्रणालियाँ शामिल थीं। इन क्षमताओं ने एक एकीकृत परिचालन परिदृश्य तैयार करने में मदद की, जिससे सभी इकाइयों में निर्णय लेने और समन्वय में सुधार हुआ।

सेना ने कहा कि इस अभ्यास ने सभी रैंकों को यथार्थवादी युद्ध स्थितियों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया और साथ ही उभरते खतरों से निपटने के लिए प्रक्रियाओं को परिष्कृत किया। लड़ाकू हथियारों, सहायक इकाइयों और सेवाओं के बीच देखा गया तालमेल आधुनिक युद्धक्षेत्र के लिए एकजुट, तकनीक-संचालित प्रतिक्रियाएँ विकसित करने के प्रयासों को रेखांकित करता है।

'वोट चोरी' पर गरमाई सियासत, राउत बोले- 90% महायुति विधायक धांधली से जीते

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने शनिवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा भाजपा पर लगाए गए 'वोट चोरी' के आरोपों को दोहराया और कहा कि महाराष्ट्र में महायुति के 90 प्रतिशत विधायक 'वोट चोरी' के कारण जीते हैं। राउत की यह प्रतिक्रिया राहुल गांधी के हालिया दावों के दो दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र से लगभग 6000 वोटों की 'वोट चोरी' का आरोप लगाया था। इस साल की शुरुआत में, कांग्रेस सांसद ने चुनाव आयोग द्वारा बेंगलुरु मध्य लोकसभा क्षेत्र से लगभग 100000 नामों को हटाने और चुनावों में धांधली करने में भाजपा की मदद करने का आरोप लगाया था।

संजय राउत ने संवाददाताओं से कहा कि महाराष्ट्र में ऐसे लोग चुने गए हैं जिनके बारे में लोगों को भी पता नहीं है कि वे विधायक हैं। वे 'वोट चोरी' के कारण विधायक बने हैं। एकनाथ शिंदे, अजित पवार या भाजपा के 90 प्रतिशत विधायक वोट चुराकर या धांधली करके विधायक बने हैं। इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राष्ट्रीय राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर 'भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने वाले

लोगों' को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि कुछ खास लोग व्यवस्थित रूप से अल्पसंख्यक समूहों के वोट काट रहे हैं जो विशेष रूप से कांग्रेस को वोट देते हैं।

कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा, 'मैं युवाओं और लोगों को स्पष्ट सबूत दिखाने जा रहा हूँ कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त उन लोगों को बचा रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। मैं आपको वोट जोड़ने और हटाने के तरीके भी दिखाऊँगा और यह भी दिखाऊँगा कि यह कैसे किया जाता है।' उन्होंने आगे कहा, 'चुनाव दर चुनाव, कोई न कोई, कुछ लोगों का समूह पूरे भारत में व्यवस्थित तरीके से मतदाताओं को निशाना बनाकर उनके नाम हटा रहा है। अलग-अलग समुदायों, खासकर जो विपक्ष को वोट दे रहे हैं, दलित, ओबीसी, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है जो विपक्ष को वोट देते हैं। हमने यह कई बार सुना है और अब हमें इसका 100 प्रतिशत प्रमाण मिल गया है। मैं इस मंच पर ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जो 100 प्रतिशत प्रमाणों पर आधारित न हो। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने देश, संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से प्यार करता है और मैं उस प्रक्रिया की रक्षा कर रहा हूं। मैं 100 प्रतिशत प्रमाणों पर आधारित नहीं होने वाला हूं, जिन्हें आप निर्धारित कर सकते हैं।'

कर्नाटक के अलंद निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात करते हुए, उन्होंने आरोप लगाया कि लगभग 6 हज़ार वोट अज्ञात लोगों द्वारा धोखाधड़ी से हटा दिए गए, जिन्होंने सॉफ़्टवेयर का इस्तेमाल करके असली मतदाताओं का रूप धारण कर लिया। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक के अलंद में, 6018 वोटों को किसी ने हटाने की कोशिश की। हमें नहीं पता कि 2023 के चुनावों में कुल कितने वोट हटाए गए, लेकिन कोई पकड़ा गया। ज़्यादातर अपराधों में, यह संयोग से पकड़ा गया। हुआ यह कि बूथ लेवल अधिकारी ने देखा कि उसके चाचा का वोट हटा दिया गया है। जब उसने जाँच की, तो उसने पाया कि उसके पड़ोसी ने वोट हटा दिया था।

किडनैपिंग केस में बड़ा एक्शन...पूर्व आईएएस पूजा खेडकर के पिता का ड्राइवर गिरफ्तार

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

नवी मुंबई पुलिस ने शहर में हाल ही में हुए रोड रेज और अपहरण मामले में पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ड्राइवर की पहचान प्रफुल्ल सालुंखे के रूप में हुई है, जिसे खेडकर के साथ छह दिनों तक फरार रहने के बाद महाराष्ट्र के धुले जिले के सिंदखेड़ से गिरफ्तार किया गया। सहायक पुलिस आयुक्त राहुल धास के अनुसार, सालुंखे को 24 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इस बीच, मुख्य आरोपी दिलीप खेडकर, उसकी पत्नी मनोरमा खेडकर और एक अन्य अज्ञात संदिग्ध की तलाश जारी है।

मामले की जाँच के तहत, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। यह मामला 13 सितंबर को हुए एक विवाद से संबंधित है, जब पीड़ित प्रह्लाद कुमार द्वारा चलाया जा रहा एक कंक्रीट मिक्सर ट्रक कथित तौर पर दिलीप खेडकर की टोयोटा लैंड क्रूज़र से टकरा गया था। घटना के बाद, खेडकर और सालुंखे ने कुमार का अपहरण कर लिया

और उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय पुणे ले गए, जैसा कि दावा किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती बहस के बाद, कुमार को नवी मुंबई से जबरन मनोरमा खेडकर के पुणे स्थित एक बंगले में ले जाया गया। पुलिस अभी तक अपहरण में इस्तेमाल की गई गाड़ी बरामद नहीं कर पाई है और आगे की पूछताछ जारी है। जाँचकर्ताओं का मानना ??है कि मनोरमा खेडकर ने इस घटना में भूमिका निभाई थी, कथित तौर पर पुलिस की राह में बाधा डालने के लिए कुत्तों को छोड़ा और अपने पति और सालुंखे को भागने में मदद की। पुणे स्थित बंगले पर पुलिस कार्रवाई के दौरान, अधिकारी शुरू में अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि मनोरमा खेडकर ने गेट खोलने से इनकार कर दिया था। अपहृत व्यक्ति, कुमार, को अंततः पुलिस ने घर के अंदर ही पकड़कर बचा लिया।

वाशी विभाग ने अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई शुरू की

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

नवी मुंबई नगर निगम के अतिक्रमण विभाग द्वारा जारी नोटिस के बावजूद, संबंधितों ने नोटिस का संज्ञान नहीं लिया। माननीय आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे के निर्देशानुसार और अतिरिक्त आयुक्त (2) डॉ. राहुल गेठे एवं उपायुक्त (अतिक्रमण) डॉ. कैलाश गायकवाड़ के मार्गदर्शन में, अतिक्रमण विभाग ने नवी मुंबई नगर निगम विभाग के माध्यम से वाशी प्रभाग में अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध बेदखली की कार्रवाई की।

नवी मुंबई नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में, जुहूगांव, सी ज़ोन वाशी में, श्रीमति रंजना मधुकर भोईर, मकान संख्या 338, जुहूगांव द्वारा नवी मुंबई नगर निगम से अनुमति लिए बिना ही अवैध रूप से भवन का निर्माण शुरू किया गया था। उक्त अनधिकृत निर्माण के लिए वाशी प्रभाग द्वारा महाराष्ट्र क्षेत्रीय योजना एवं नगर नियोजन अधिनियम, 1966 की धारा 54 के अंतर्गत एक नोटिस जारी किया गया था। संबंधितों द्वारा किए गए अनधिकृत निर्माण को स्वयं हटाना आवश्यक था। लेकिन उन्होंने अनधिकृत निर्माण जारी रखा। उक्त अनाधिकृत निर्माण पर वाशी प्रभाग द्वारा तोड़फोड़ अभियान चलाकर अनाधिकृत निर्माण को आंशिक रूप से ध्वस्त किया गया। इस तोड़फोड़ अभियान में सी प्रभाग कार्यालय के सहायक आयुक्त श्री सुखदेव येदवे, कनिष्ठ अभियंता श्री मंगेश मेहर के साथ-साथ अतिक्रमण विभाग, अतिक्रमण पुलिस और स्थानीय पुलिस के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे। इस तोड़फोड़ अभियान में 01 जेसीबी, कुल 15 मजदूर, 08 कंक्रीट, 02 ब्रेकर और 01 गैस कटर का उपयोग किया गया।

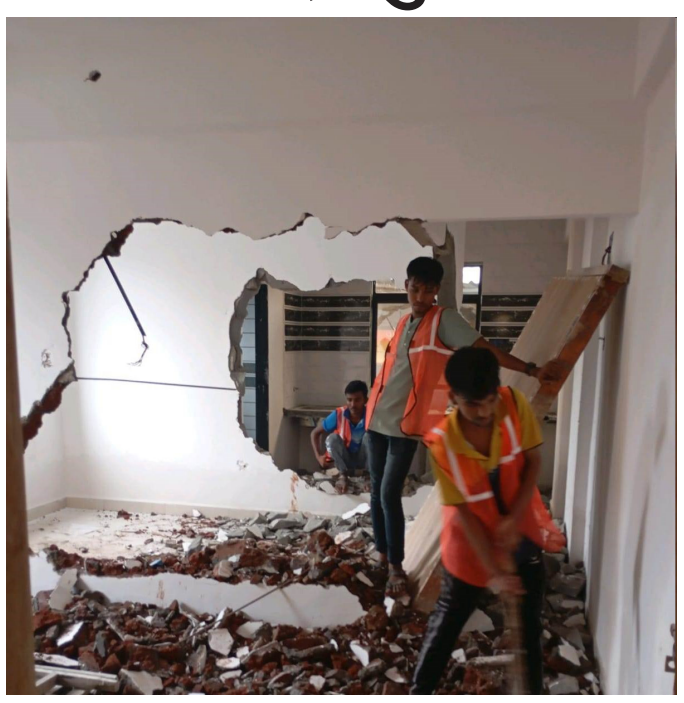

आगे भी इसी प्रकार अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई तेज की जाएगी।

बावनकुले बोले- निजी कंपनी भी पट्टे पर ले सकेगी बंजर आदिवासी जमीन, कानून बनाएगी सीएम फडणवीस की सरकार

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि जल्द ही राज्य के आदिवासी अब अपनी बंजर जमीन निजी कंपनियों को पट्टे पर दे सकेंगे। इस फैसले का उद्देश्य आदिवासियों की आय बढ़ाना और उन्हें जमीन के मालिकाना हक से वंचित किए बिना अतिरिक्त आमदनी दिलाना है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि इसके लिए जल्द ही एक कानून लाया जाएगा।

कांग्रेस ने हालांकि इस कदम पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार का यह निर्णय आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के बजाय बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाएगा और आदिवासियों का शोषण होगा। वहीं सरकार का कहना है कि यह कदम आदिवासियों को सीधी आमदनी और लंबे समय तक सुरक्षा देगा।

सरकार बोली- आय का नया अवसर

बावनकुले ने नागपुर में संवाददाताओं से कहा कि आदिवासी किसानों को इस फैसले से सीधा फायदा होगा। यदि कोई आदिवासी किसान किसी उद्योगपति के साथ साझेदारी में अपनी जमीन विकसित करना चाहता है, तो अब वह सीधे जिला कलेक्टर से अनुमति लेकर ऐसा कर सकेगा। पहले ऐसी सभी मंजूरियां मंत्रालय (मंत्रालय मुंबई) से लेनी पड़ती थीं, जिससे प्रक्रिया लंबी और जटिल हो जाती थी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रस्तावित कानून केवल बंजर जमीन पर लागू होगा। उपजाऊ जमीन को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि उन्हें पालघर और नंदुरबार जिलों के कई आदिवासी जमीन मालिकों से अनुरोध मिले हैं।

सोलर प्रोजेक्ट्स और सालाना आमदनी

बावनकुले ने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई निजी कंपनी सरकारी योजना के तहत सोलर पैनल लगाना चाहती है, तो वह सीधे आदिवासी जमीन मालिक के साथ समझौता कर सकती है। जमीन का मालिकाना हक आदिवासी के पास ही रहेगा और उसे हर साल निश्चित राशि के रूप में भुगतान मिलेगा। उन्होंने कहा कि बंजर जमीन से ऐसी आमदनी पहले संभव नहीं थी, लेकिन अब इससे जीवन स्तर सुधर सकता है।

मालिकाना हक रहेगा सुरक्षित

राजस्व मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित कानून में मालिकाना हक पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। यदि जमीन लंबे समय के लिए पट्टे पर दी जाती है, तब भी मालिक को हर साल तय रकम मिलती रहेगी। इससे आदिवासी जमीन का हक नहीं खोएंगे।

उन्होंने बताया कि समझौते में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर की भूमिका अनिवार्य होगी। यही नहीं, न्यूनतम पट्टा किराया प्रति एकड़ 50,000 रुपये या प्रति हेक्टेयर 1,25,000 रुपये सालाना तय किया गया है। किसान और निजी कंपनी चाहें तो आपसी सहमति से इससे ज्यादा रकम भी तय कर सकते हैं।

खनिज उत्खनन का भी प्रावधान

बावनकुले ने कहा कि यदि किसी आदिवासी की जमीन पर बड़े या छोटे खनिज पाए जाते हैं, तो किसान निजी कंपनियों के साथ एमओयू कर सकेंगे। इसमें उन्हें प्रति टन या प्रति ब्रास (खनिज की माप) पर मुनाफा मिलेगा। हालांकि इस लाभ की सटीक मात्रा अभी तय नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की नीति बनाई जा रही है, जिससे आदिवासी समुदाय को स्थायी आय मिले और उनका हक भी सुरक्षित रहे।

इस फैसले पर कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व मंत्री विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि यह निर्णय मूल रूप से कुछ खास उद्योगपतियों और प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए लिया गया है। उनका कहना है कि इस कानून का इस्तेमाल कर आदिवासियों का शोषण किया जाएगा और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा।

मुंबई में बुलेट ट्रेन सुरंग का उद्घाटन, वैष्णव बोले- अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी होगी परियोजना

मुंबई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत निर्मित शिलफाटा और घनसोली के बीच 4.88 किलोमीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उसी तरह लाभकारी साबित होगी, जैसे छह दशक पहले जापान को लाभ मिला था। सुरंग निर्माण को वैष्णव ने ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि सूरत-बिलिमोरा खंड पर हाई-स्पीड कॉरिडोर का पहला चरण दिसंबर 2027 में शुरू होगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टोक्यो, नागोया और ओसाका जैसे प्रमुख केंद्रों को जोड़ने वाली दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन ने जापान की पूरी अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव डाला है। ऐसे ही यह परियोजना आणंद, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वापी और मुंबई को एकल आर्थिक गलियारे के तौर पर विकसित करेगी।

उन्होंने कहा कि इससे एकीकृत बाजार का निर्माण होगा। पूरे मार्ग पर आर्थिक विकास में तेजी आएगी। साथ ही आर्थिक एकीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। उच्च उत्पादकता और व्यवसाय विस्तार के माध्यम से आर्थिक लाभ प्रारंभिक निवेश से कहीं अधिक होगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि घनसोली और शिलफाटा की ओर से एक साथ सुरंग की खुदाई की गई। टीमों चुनौतीपूर्ण ढंग से पानी के नीचे काम किया। यह परियोजना अत्याधुनिक इंजीनियरिंग नवाचारों को बढ़ाती है। दो बुलेट ट्रेनों के लिए एकल सुरंग तकनीक का उपयोग

और पुल निर्माण में 40-मीटर गर्डरों को लगाना महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि परियोजना में जापानी साझेदारों ने इस तकनीकी नवाचार की दक्षता और डिजाइन की तारीफ की है। भारत ने इसकी पूरी जानकारी हासिल कर ली है। मैंने परियोजना की समीक्षा के लिए जापानी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों पक्षों ने प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में नवीनतम ई10 शिंकानसेन (जापान की अगली पीढ़ी की बुलेट ट्रेन) शुरू करने पर भी चर्चा हुई। जापान ने भारत को यह उन्नत रेल प्रणाली उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की है।

किराया उचित होगा, मध्यम वर्ग को होगा लाभ

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बुलेट ट्रेन मध्यम वर्ग के परिवहन के लिए होगी। इसका किराया उचित होगा। गूगल मैप पर मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय नौ घंटे दिखाया गया है, लेकिन बुलेट ट्रेन से लोग यह दूरी दो घंटे सात मिनट में तय कर सकेंगे।

वैष्णव ने कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना का पहला चरण 2027 में सूरत-बिलिमोरा खंड पर शुरू किया जाएगा। यह 2028 में ठाणे और 2029 में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को कवर करेगा। 320 किलोमीटर पुल का निर्माण पूरा हो चुका है। सभी जगह स्टेशन का निर्माण तेजी से चल रहा है।

उन्होंने कहा कि नदी पुलों का निर्माण किया जा रहा है। साबरमती सुरंग का निर्माण कार्य भी लगभग पूरा होने वाला है। सेवाओं को इस तरह डिजाइन किया गया है कि सुबह और शाम के व्यस्त समय में हर आधे घंटे में एक ट्रेन चलेगी। एक बार पूरा नेटवर्क स्थिर हो जाए, तो व्यस्त समय में हर 10 मिनट में एक ट्रेन चलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा के लिए टिकट आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होगी और यात्री स्टेशन पर आकर ट्रेन में चढ़ सकेंगे।

बटन दबाकर किया विस्फोट और सुरंग शुरू हुई

उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घनसोली शाफ्ट स्थित सुरंग के एक द्वार पर खड़े होकर बटन दबाया। इसके बाद डायनामाइट विस्फोट हुआ। जिससे सुरंग की अंतिम परत टूट गई और पांच किलोमीटर की खुदाई पूरी हो गई।

ऑस्ट्रियन टनल विधि से खोदी गई सुरंग न्यू ऑस्ट्रियन टनल मेथड (एनएटीएम) का उपयोग करके खोदी गई यह सुरंग, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) और शिलफाता के बीच 21 किलोमीटर लंबे भूमिगत खंड का हिस्सा है। इसमें ठाणे क्रीक के नीचे सात किलोमीटर का खंड भी शामिल है। बुलेट ट्रेन सुरंग अब सावली शाफ्ट को शिलफाटा में सुरंग पोर्टल से जोड़ती है।

एनएचएसआरसीएल ने कहा कि सुरंग की खुदाई मई 2024 में तीन चरणों में शुरू हुई थी, और 2.7 किलोमीटर के खंड की पहली सफलता नौ जुलाई को हासिल की गई थी। घनसोली और शिलफाता दोनों तरफ से एक साथ खुदाई के लिए एक अतिरिक्त मध्यवर्ती सुरंग (एडीआईटी) का निर्माण किया गया था।

कहा गया है कि एनएटीएम सुरंग की आंतरिक चौड़ाई 12.6 मीटर है और इसका निर्माण चुनौतीपूर्ण भूवैज्ञानिक परिस्थितियों में ड्रिलिंग, विस्फोट, सर्वेक्षण कार्यों और सहायक प्रणालियों का उपयोग करके किया गया है। निगम ने कहा कि अगले चरण में वॉटरप्रूफिंग, लाइनिंग, फिनिशिंग और उपकरण स्थापना का काम शामिल होगा, जबकि शेष 16 किलोमीटर सुरंग निर्माण का काम टनल बोरिंग मशीनों (टीबीएम) का उपयोग करके किया जाएगा।

मध्य रेल के सोलापुर मंडल ने 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान' के अंतर्गत मंडल रेलवे अस्पताल में महिला कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया

मुंबई। मध्य रेल के सोलापुर मंडल ने 18 सितंबर 2025 को डॉ. कोटनीस मेमोरियल मंडल रेलवे अस्पताल (डीआरएच), सोलापुर में 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान' के अंतर्गत महिला कर्मचारियों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। इसका उद्देश्य परिवारों की कल्याण और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने में महिलाओं के स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर देना था।

शिविर में महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच सेवाएँ प्रदान की गईं, जिनमें हीमोग्लोबिन परीक्षण, रक्तचाप

की निगरानी और परामर्श सत्र शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान कुल 53 लाभार्थियों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। चिकित्सा दल ने प्रतिभागियों की विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों की पहचान की और उन्हें परामर्श दिया। जागरूकता अभियान के तहत, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विषयों पर व्याख्यान दिए गए, जिनमें शामिल हैं: - मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य - पोषण एवं जीवनशैली प्रबंधन - मासिक धर्म स्वच्छता - एनीमिया की रोकथाम इस पहल ने न केवल समय पर निदान और मार्गदर्शन प्रदान किया, बल्कि निवारक स्वास्थ्य सेवा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच भी तैयार किया, जिससे महिला सशक्तिकरण और पारिवारिक कल्याण में योगदान मिला। शिविर का उद्घाटन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, डीआरएच सोलापुर डॉ. मंजूनाथ जी.एस., सहायक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, डीआरएच सोलापुर डॉ. कृष्णा आर. चंडक और अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों की उपस्थिति में हुआ। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, डॉ. कृष्णा आर. चंडक ने इस पहल का मुख्य संदेश दिया और इस बात पर ज़ोर दिया कि महिलाओं का स्वास्थ्य एक मजबूत समाज की रीढ़ है। 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान' के तहत यह प्रयास सोलापुर मंडल की अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो एक स्वस्थ और सशक्त कार्यबल को बढ़ावा देने के भारतीय रेलवे के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है।

पश्चिम रेलवे

मरम्मत एवं प्रतिस्थापन कार्य

वरिष्ठ डीईई/पी/मुंबई सेंट्रल, मुंबई ई-निविदा संख्या: EL-Maint-81-839-WA-10 दिनांक 17-09-2025 आमंत्रित करता है। **कार्य एवं स्थान: मुंबई डिवीजन उपनगरीय खंड:** मुंबई सेंट्रल स्थित जगजीवनराम अस्पताल सहित चर्चगेट और विरार के बीच 2 वर्षों के लिए विभिन्न स्थानों पर विभिन्न ब्रांडों और क्षमताओं के वाटर कूलरों की मरम्मत, दोषपूर्ण पुर्जों का प्रतिस्थापन और सफाई का कार्य। **कार्य की अनुमानित लागत:** 71,20,443/- **बयाना राशि:** 1,42,400/- **जमा करने की तिथि एवं समय:** 13.10.2025, 15:00 बजे तक। **खोलने की तिथि एवं समय:** 13.10.2025 को 15:30 बजे। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएं। 0613

हमें फॉलो करें facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे वडोदरा मंडल

रोड अंडर ब्रिज का प्रावधान करने द्वारा समपार फाटकों का निरसन

ई–निविदा सूचना सं. DRM-BRC 124 OF 2025-26

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिए मंडल रेल प्रबंधक (W A/C), पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा–390 004 द्वारा निम्नानुसार कार्यों हेतु मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं । **कार्य का नाम:** आणंद–गोधरा अनुभाग :– रोड अंडर ब्रिज का प्रावधान करने द्वारा 08 नंग समपार फाटकों (LC सं. 2, 10, 13, 17, 38, 48, 54A, 64) का निरसन । **कार्य की अनुमानित लागत (₹ में):** 41,99,47,460.44 **जमा कराने की बीड सुरक्षा (₹ में):** 22,49,700.00 **निविदा जमा कराने एवं निविदा खोलने की तिथि एवं समय:** निविदा दिनांक **13.10.2025** को 15:00 बजे से पहले जमा की जाएगी एवं उसी दिनांक को 15:30 बजे निविदा खोली जाएगी । **वेबसाईट का विवरण एवं नोटीस का स्थान जहाँ से विवरण देखे जा सकते हैं एवं कार्यालय का पता जहाँ से निविदा प्रपत्र खरीद सकते हैं: वेबसाईट: www.ireps.gov.in** मंडल रेल प्रबंधक (W A/C), पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा–4

BRC-196

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

मध्य रेल

सोलापुर मंडल

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर, सामान्य, मध्य रेल, सोलापुर, निम्नलिखित कार्य के लिए ख्याति प्राप्त, अनुभवी और लाईसेंसधारी विद्युत ठेकेदारों से रेलवे की ई-प्रोक्यूरमेंट वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रित करते हैं। **(1) निविदा क्र.: सोला/वि/नि/2024/48R1. कार्य का नाम:** सोलापुर मंडल में स्थित 5 गुड्स शेड में ट्रैक के किनारे प्रकाश व्यवस्था के साथ-साथ 6 गुड्स शेड में हाईमास्ट प्रकाश व्यवस्था के संबंध में विद्युत सामान्य सेवा भाग का कार्य। (पुनः आमंत्रण) **कार्य की लागत:** ₹ 72,24,829.76. **बोली प्रतिभूति:** ₹1,44,500/-. **कार्य पुरा करने की अवधि:** 06 माह। **निविदा प्रस्ताव की वैधता:** 60 दिन। **(2) निविदा क्र.: सोला/वि/नि/2025/14. कार्य का नाम:** सोलापुर डिवीजन के कुर्दुवाड़ी स्टेशन पर रेलवे अस्पताल के निर्माण के संबंध में विद्युत सामान्य सेवा भाग का कार्य। **कार्य की लागत:** ₹ 24,96,155.16. **बोली प्रतिभूति:** ₹49,900/-. **कार्य पुरा करने की अवधि:** 12 माह। **निविदा प्रस्ताव की वैधता:** 60 दिन। **(3) निविदा क्र.: सोला/वि/नि/2025/15. कार्य का नाम:** सोलापुर डिवीजन के लातूर स्टेशन पर 20 बिस्तरों वाले आरपीएफ बैरक के संबंध में विद्युत सामान्य सेवा भाग का कार्य। **कार्य की लागत:** ₹ 24,19,672.07. **बोली प्रतिभूति:** ₹48,400/-. **कार्य पुरा करने की अवधि:** 12 माह। **निविदा प्रस्ताव की वैधता:** 60 दिन। **वेबसाइट पर निविदा बंद करने की तिथि और समय:** दि. **13/10/2025** को **15.00 बजे।** बोली प्रतिभूति राशि की रकम का भुगतान ई-पेंमेंट द्वारा वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर करना है।

वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (सा) सोलापुर

Sai/SUR/58

रेलवे फाटक को बंद स्थिति में पार करना मना है

नशे से संबंधित अपराधों में शून्य सहनशीलता महत्वपूर्ण

कानून-व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन से महाशक्ति बनने की ओर देश का मार्ग- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

कानून-व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन से देश महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो सकता है। कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए, नशे से संबंधित अपराध पुलिस बल के लिए एक चुनौती बनते जा रहे हैं और इसके लिए राज्य ने शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई है। साथ ही, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बदलते समय के अनुरूप साइबर क्षेत्र में अपराधों को सुलझाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग आवश्यक है।

भारतीय पुलिस फाउंडेशन के 10वें स्थापना दिवस के अवसर पर पुलिस मुख्यालय, कोलाबा में 'भारत के आर्थिक विकास के लिए पुलिस बल की पुनर्कल्पना' विषय पर एक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोल रहे थे। उत्तर प्रदेश के सामाजिक न्याय राज्य मंत्री असीम अरुण, भारतीय पुलिस फाउंडेशन के प्रमुख और मेघालय के पूर्व राज्यपाल आर.एस. मशारी, फाउंडेशन के अध्यक्ष ओ.पी. सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक, राज्य पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला, मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती और विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने कहा कि उन्हें गर्व है कि महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस ने हमेशा उच्च मानदंड बनाए रखे हैं। यह सराहनीय है कि पुलिस आज भारत के आर्थिक विकास पर चर्चा कर रही है और आज के कार्यक्रम में आयोजित विचार-मंथन सत्र पुलिस बल में और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने यह भी कहा कि सरकार इस विचार-मंथन से निकलने वाले नए उपायों पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी।

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने कहा कि पुलिस बल के साथ-साथ समाज में भी एकता होनी चाहिए। इससे समाज में नकारात्मकता कम होगी और राज्य और देश सतत प्रगति की ओर बढ़ सकेंगे। समय के साथ अपराधों का स्वरूप बदला है और पुराने समय के सतत मूल्यों के साथ-साथ नई तकनीक का उपयोग किया जाए तो प्रगति संभव है। तदनुसार, 2023 में एक नया पुलिस संगठनात्मक ढांचा तैयार किया गया है। अपराधों को तेज़ी से सुलझाने में मदद के लिए

एक अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा प्रयोगशाला स्थापित की गई है। अन्य देशों ने भी हमारे राज्य जैसी प्रयोगशाला स्थापित करने की मांग की है। एआई की मदद से जटिल अपराध के मामलों का तेज़ी से समाधान हो रहा है। देश और राज्य की तीनों पुलिस बल सक्षम होने के कारण, नशे के ज़रिए अपराध बढ़ रहे हैं और युवाओं को निष्क्रिय बनाया जा रहा है। आज, नशे से जुड़े अपराध पुलिस बल के सामने एक चुनौती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें जीरो टॉलरेंस ज़रूरी है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि संविधान पुलिस व्यवस्था में जाँच और संतुलन का प्रावधान करता है और कई अधिकारियों ने उपलब्ध कानूनों का उपयोग करके परिवर्तनकारी सुधार किए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि चूँकि आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल के कानून हैं, इसलिए लोकतंत्र के आधार पर उनमें आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। पुलिस की भूमिका को और प्रभावी बनाने के लिए नई तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना ज़रूरी है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपराध बढ़ रहे हैं और ऑनलाइन अपराधों पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी नई तकनीकों और विधियों का उपयोग आवश्यक है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। आज भी कृषि क्षेत्र उतना ही महत्वपूर्ण है और बदलते समय के साथ अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र पर निर्भर है। राज्य या देश की अर्थव्यवस्था 55 से 65 प्रतिशत तक सेवा क्षेत्र पर निर्भर करती है। इन दोनों क्षेत्रों पर आधारित अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ अलग-अलग हैं। इसलिए बदलते सेवा क्षेत्र की परिभाषा को समझना आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने कहा कि पुलिस बल के आधुनिकीकरण के साथ-साथ स्थायी मूल्यों को बनाए रखने के प्रयास भी किए जाने चाहिए।

इस दौरान, पुलिस प्रशासन, डिजिटल सीमाओं की सुरक्षा: निवेश पारिस्थितिकी तंत्र और विश्व में स्थिरता बनाने के लिए रणनीतिक पुलिस-उद्योग सहयोग की आवश्यकता जैसे विषयों पर चर्चा की गई।

2015 मुम्ब्रा हत्या केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा को पलटा, आरोपी को किया बरी

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2015 में मुंबई रेलवे स्टेशन के पास अपने दोस्त की हत्या के आरोपी एक व्यक्ति की आजीवन कारावास की सजा को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि अभियोजन पक्ष का मामला एक संदिग्ध प्रत्यक्षदर्शी के बयान और मृत्युपूर्व दिए गए एक अविश्वसनीय बयान पर आधारित था। रियाज़ उर्फ ??बबलू मुजावर को 16 अप्रैल, 2015 को अपने दोस्त रोहित जाधव पर एक पुराने झगड़े के बाद कई बार चाकू मारने का दोषी ठहराया गया था।

पुलिस ने बताया कि एक स्थानीय पान स्टॉल मालिक ने झगड़ा देखा और हमलावर के रूप में रियाज़ की पहचान की। रोहित के भाई रोशन ने बाद में दावा किया कि पीड़ित ने बेहोश होने से पहले रियाज़ का नाम लिया था। जाँचकर्ताओं ने कथित तौर पर आरोपी की निशानदेही पर बरामद एक चाकू ज़ब्त कर लिया, जिस पर रोहित का ब्लड ग्रुप लगा हुआ था।

हालाँकि, न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की खंडपीठ ने अभियोजन पक्ष के मामले में गंभीर खामियाँ पाईं। उन्होंने कहा कि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी को उसका बयान दर्ज होने से पहले आधी रात से सुबह 9 बजे तक पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया था। पीठ ने कहा कि इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह संभव है कि उसका बयान दबाव में दर्ज किया गया हो या अपनी जान बचाने के लिए दिया गया हो। इन परिस्थितियों में, हम उसके साक्ष्य पर भरोसा नहीं कर सकते। अदालत ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दिया। फेफड़े और लीवर पर गहरे चाकू के घाव दर्ज थे। न्यायाधीशों ने कहा, 'यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल था कि मृतक कुछ भी बोल पाने की स्थिति में हो, हमलावर का नाम लेकर घटना का वर्णन करना तो दूर की बात है।

'सोशल मीडिया पोस्ट हटाने, माफी मांगने का यह मतलब नहीं कि मामला रद्द कर दिया जाए';हाईकोर्ट की टिप्पणी

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट के लिए छात्रा (19) के खिलाफ मामला केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि उसने पोस्ट हटा लिया है और इसके लिए माफी मांग ली है।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अखंड की पीठ ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि आरोपी मेधावी छात्रा है और उसने अपनी परीक्षाएं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की जा सकती है। पीठ पुणे की एक छात्रा की दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत-पाकिस्तान शत्रुता पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए मई में उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। उसे गिरफ्तार किया गया था लेकिन बाद में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उसे रिहा कर दिया गया था।

छात्रा के वकील ने शुक्रवार को अदालत को बताया कि जमानत मिलने के बाद वह परीक्षा में शामिल हुई और उसे अच्छे अंक मिले। हालांकि पीठ ने कहा कि इसलिए कि वह एक मेधावी छात्रा है, प्राथमिकी रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। छात्रा के वकील ने दलील दी कि पोस्ट के पीछे उसकी कोई बुरी मंशा नहीं थी और उसने तुरंत इसे हटा दिया और माफी मांग ली। हालांकि, अदालत ने कहा कि पोस्ट को हटाने से मामला और भी गंभीर और जटिल हो गया

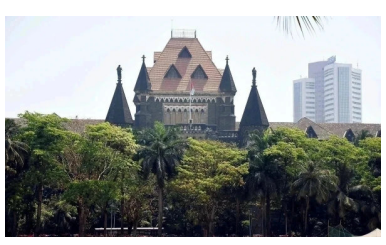

है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद निर्धारित की और सरकारी वकील मनखुवर देशमुख को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया।

छात्रा ने 7 मई को इंस्टाग्राम पर रिफॉर्मिस्तान नाम के एक अकाउंट से एक पोस्ट को रीपोस्ट किया था, जिसमें भारत सरकार की आलोचना की गई थी। दो घंटे के अंदर छात्रा को अपनी गलती का अहसास हुआ और कई धमकियां मिलने के बाद उसने पोस्ट हटा दिया।

अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के अवसर पर, 1,000 से अधिक नागरिकों और छात्रों ने भाग लिया और तटों की सफाई की

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

उत्तर से दक्षिण तक फैले नवी मुंबई शहर के पश्चिम में एक विस्तृत तटीय पट्टी है। इसी के अनुरूप, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के अवसर पर, नवी मुंबई नगर निगम द्वारा आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे के मार्गदर्शन में 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के अंतर्गत विशेष सफाई अभियान आयोजित किए गए। हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को दुनिया भर में 'अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस' मनाया जाता है। इस अवसर पर, आज, 1,000 से अधिक नागरिकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ, अतिरिक्त आयुक्त श्री सुनील पवार के नेतृत्व में, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपायुक्त डॉ. अजय गाडे ने विभिन्न विभागों के तटों पर आयोजित इन अभियानों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया और अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले छात्रों और नागरिकों का उत्साह बढ़ाया। मुख्य स्वच्छता अधिकारी श्री राजेंद्र इंगले और सभी विभागों के स्वच्छता अधिकारियों, स्वच्छता निरीक्षकों, उप स्वच्छता निरीक्षकों ने सभी अभियानों के आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इसमें बेलापुर संभाग के षष्ठम आयुक्त श्री अमोल पलावे और स्वच्छता

अधिकारी श्री नरेश अंधेर के प्रयासों से, जनभागीदारी पर बल देते हुए, दिवाले ग्राम जेट्टी और डोलया बीच, दो स्थानों पर गहन सफाई अभियान चलाया गया। दिवाले ग्राम जेट्टी में हुए इस अभियान में नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों के साथ-साथ एनसीआरडी स्टर्लिंग कॉलेज नेरुल, विद्या उत्कर्ष मंडल कॉलेज बेलापुर, एमजीएम कॉलेज कामोठे, तिलक कॉलेज नेरुल, भारती विद्यापीठ इंजीनियरिंग कॉलेज खारघर, सरस्वती इंजीनियरिंग कॉलेज खारघर के एनएसएस इकाई, डीएलएलई एसआईईएस कॉलेज नेरुल, एसओआई कॉलेज की एनएसएस इकाई, एमजीएम सीईटी की एनएसएस इकाई, डी.डी. विस्पुते कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च सेंटर, सकलीवाल फाउंडेशन कॉलेज के छात्रों और नागरिकों के 250 से अधिक स्वच्छता प्रेमियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

वाशी के सेक्टर 8 में षष्ठम आयुक्त श्री सुखदेव येदवे और स्वच्छता अधिकारी श्री जयश्री आढाल के माध्यम से सागर विहार क्षेत्र में विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों की भागीदारी के साथ इसी प्रकार का अभियान चलाया गया। यहाँ भी अभियान में भाग लेने वाले युवाओं की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। एग्नेल स्कूल ऑफ लॉ, वाशी की एनएसएस इकाई के छात्र, तिलक कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स के छात्र, उनके ग्रीन क्लब, रोटरी क्लब के पदाधिकारी और सदस्यों सहित 250 से अधिक नागरिकों ने इस अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

नेरुल में सारसोले जेट्टी समुद्रतट क्षेत्र में षष्ठम आयुक्त श्री जयंत जावड़ेकर और स्वच्छता अधिकारी श्री अरुण पाटिल द्वारा विभाग के सहकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसमें एचडीएफसी बैंक नेरुल और दुर्गा फाउंडेशन के 200 से अधिक सदस्यों और नागरिकों ने भाग लिया।

ऐरोली प्रभाग में, मैरीटाइम सर्विसेज एसोसिएशन के सदस्यों और सुशीलादेवी देशमुख महाविद्यालय के 150 से अधिक विद्यार्थियों ने षष्ठम आयुक्त श्री सुनील कथोले और स्वच्छता अधिकारी श्री सुषमा देवधर द्वारा मुलुंड कटाई ब्रिज के नीचे सेक्टर 10 और 14 के बीच के क्षेत्र में चलाए गए व्यापक स्वच्छता अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

17 सितंबर से 02 अक्टूबर 2025 तक एक पखवाड़े के लिए घोषित 'स्वच्छ भारत मिशन' अभियान 'स्वच्छता ही सेवा 2025' के अंतर्गत, नवी मुंबई नगर निगम, आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे के मार्गदर्शन में, प्रतिदिन विभिन्न स्वच्छता गतिविधियों का क्रियान्वयन कर रहा है और नागरिकों से बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की जा रही है।

गरबा में केवल हिंदू वाले विहिप के परामर्श पर रार, भाजपा बोली- आयोजकों का हक, कांग्रेस बिफरी

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। महाराष्ट्र में विश्व हिंदू परिषद के गरबा कार्यक्रम में केवल हिंदू वाले परामर्श को लेकर रार छिड़ गई है। विहिप ने नवरात्र गरबा कार्यक्रम के आयोजकों को सलाह जारी की है। इसमें कहा गया है कि गरबा कार्यक्रमों में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाए। साथ ही प्रवेश करने वालों के आधार कार्ड की जांच करें। विहिप की इस सलाह का भाजपा ने समर्थन किया है। जबकि कांग्रेस ने विहिप पर आरोप लगाए हैं।

पहले समझिए विहिप की सलाह

देशभर में नवरात्र 22 सितंबर से एक अक्तूबर तक मनाई जाएगी। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीराज नायर ने कहा कि गरबा महज एक नृत्य नहीं है। बल्कि देवी को प्रसन्न करने की पूजा का एक रूप है। मुसलमानों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि वे लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। केवल उन्हीं लोगों को इसमें भाग लेने की अनुमति दी जानी

चाहिए, जो इन अनुष्ठानों में आस्था रखते हैं।

विहिप ने गरबा आयोजकों को परामर्श जारी कर प्रवेश द्वार पर आधार कार्ड की जांच करने, प्रतिभागियों को तिलक लगाने और प्रवेश से पहले पूजा करने को कहा है। नायर ने कहा कि विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता आयोजनों पर नजर रखेंगे। गरबा पूजा का एक रूप है, मनोरंजन नहीं। जिन लोगों की देवी में आस्था नहीं है, उन्हें इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए।

भाजपा के मंत्री की प्रतिक्रिया

विहिप के रुख पर भाजपा के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, 'गरबा आयोजनों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना आयोजन समितियों के अधिकार में है।' यह उनका अधिकार है। बशर्ते उन्होंने आयोजन के लिए पुलिस से अनुमति ली हो। आयोजन समितियों को इसके आधार पर निर्णय लेना चाहिए।

महाराष्ट्र भाजपा मीडिया प्रमुख नवनाथ बान ने कहा कि गरबा एक हिंदू आयोजन है। अन्य धर्मों के लोगों को हिंदुओं द्वारा गरबा करने और देवी की पूजा करने में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हम देवी की पूजा करते हैं। वे हमारी मां के समान हैं। बान ने शिवसेना नेता संजय राउत के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वह एक विशेष समुदाय के वोटों पर नजर रखकर इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन लोग उन्हें या उनकी पार्टी को नहीं बख्शेंगे।

कांग्रेस ने क्या कहा?

इस मुद्दे पर महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल के नेता और राज्य के पूर्व मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि विहिप समाज में आग लगाना चाहती हैं। वे धर्म के नाम पर समाज को बांटना चाहते हैं और इससे राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। इस संगठन का जन्म ही देश को अस्थिर करने के इरादे से हुआ है। वडेट्टीवार ने दावा किया कि विहिप जैसे संगठनों का ऐसा रुख भारत की विविधता में एकता की नींव को हिला देता है। यह सरकार के रुख को भी दर्शाता है।

इस पर भाजपा नेता ने पलटवार करते हुए कहा कि वडेट्टीवार को पता होना चाहिए कि कांग्रेस का लोगों को बांटने का इतिहास रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने समाज में दरार पैदा की। महा विकास अघाड़ी सरकार मराठा आरक्षण की रक्षा करने में विफल रही।

'राहुल ने सच उजागर किया, आयोग को...', वोट चोरी के आरोपों पर अंबादास दानवे ने ECI से मांगा जवाब

मुंबई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों ने देशभर की सियासत में गर्माहट तेज कर दी है। मामले में आरोप-प्रत्यारोप भी अपने चरम पर है। इसी बीच शिवसेना (यूबीटी) के नेता अंबादास दानवे ने भी राहुल गांधी के आरोपों को सही बताते हुए चुनावों में कथित वोट घोटाले को लेकर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने क्यों नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग से सिर्फ एक मूल सवाल पूछ रहे हैं, वे कर्नाटक सीआईडी को जानकारी क्यों नहीं दे रहे, जो अकलकोट में वोट चोरी के आरोपों की जांच कर रही है?

क्या है राहुल गांधी के आरोप, समझिए

बता दें कि बीते 18 सितंबर को दिल्ली में प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाया कि वे भारतीय लोकतंत्र को खत्म

कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों को पुख्ता सबूतों पर आधारित बताया और चुनाव आयोग पर राजनीतिक बातें करने का आरोप लगाया।

मामले में दावने ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि आरोप बेबुनियाद नहीं हैं। राहुल गांधी ने सब कुछ ठोस सबूतों के साथ पेश किया है। उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है, बल्कि सच को सामने लाया है। चुनाव आयोग को इस पर सफाई देनी चाहिए ना कि राजनीतिक भाषा बोलनी चाहिए।

कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल के आरोप

इससे पहले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी चुनाव आयोग से तीखे सवाल पूछे थे। उन्होंने कहा था कि आयोग कर्नाटक की अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के सवालों का जवाब करने वालों की रक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ समूह कांग्रेस को वोट देने वाले अल्पसंख्यकों के वोटों को सुनियोजित तरीके से काट रहे हैं।

उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक की अलंद विधानसभा सीट में कम से कम 6,018 वोट हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक बूथ स्तर की अधिकारी को पता चला कि उसके चाचा का वोट गायब है। जब उसने जांच की तो पाया कि उसका पड़ोसी खुद ही लोगों के वोट काट रहा था। ये सब एक संयोग से पकड़ा गया।

चुनाव आयोग ने खारिज किया आरोप

हालांकि एक बार फिर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि कोई भी आम व्यक्ति ऑनलाइन वोट नहीं हटा सकता।

मध्य रेल के सोलापुर मंडल पर उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा 'हिंदी पखवाड़ा'

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मध्य रेल के सोलापुर मंडल पर 15 सितम्बर से 30 सितम्बर 2025 तक 'हिंदी पखवाड़ा' बड़े उत्साह और सक्रिय सहभागिता के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं बैठकों का आयोजन कर कर्मचारियों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

16 एवं 17 सितम्बर 2025 को मंडल कार्यालय में राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी आलेखन टिप्पण, हिंदी निबंध लेखन, हिंदी वाक् प्रतियोगिता तथा राजभाषा प्रश्न मंच का आयोजन किया गया। इसके बाद 18 एवं 19 सितम्बर 2025 को शाखाओं में टेबल ट्रेनिंग तथा कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को हिंदी कुंजीयन एवं वॉइस टाइपिंग का प्रशिक्षण दिया गया। इसी क्रम में 22 से 30 सितम्बर 2025 तक मंडल के बड़े स्टेशनों (सोलापुर, कुर्डुवाडी, पंढरपुर, लातूर, कलबुरगि एवं वाडी) पर स्थित डिपो/कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए हिंदी सुलेखन एवं राजभाषा प्रश्न मंच प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं।

19 सितम्बर 2025 को मंडल में हिंदी दिवस समारोह और मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सोलापुर की 102वीं तिमाही बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक मंडल रेल प्रबंधक डॉ. सुजीत मिश्रा की अध्यक्षता एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक तथा मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री अंशुमाली कुमार की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुई।

इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री अंशुमाली कुमार ने महाप्रबंधक महोदय का 'हिंदी दिवस संदेश' वाचन किया तथा मंडल रेल प्रबंधक डॉ. सुजीत मिश्रा द्वारा मंडल की राजभाषा त्रैमासिक ई-पत्रिका 'संदेश' के 21वें अंक का

विमोचन किया गया। अपने संबोधन में मंडल रेल प्रबंधक महोदय ने कहा कि सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करते समय कठिन शब्दों से बचते हुए सरल, सुबोध और बोलचाल की हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कर्मचारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन के माध्यम से संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन में पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया।

बैठक को संबोधित करते हुए अपर मंडल रेल प्रबंधक एवं मुख्य राजभाषा अधिकारी ने कहा कि हमारी संविधान सभा ने 14 सितम्बर 1949 को हिंदी को देश की सरकारी भाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए यह हम सबका दायित्व है कि हम अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करें।

इस अवसर पर अधिकारियों को फादर कामिल बुल्के द्वारा लिखित अंग्रेजी-हिंदी शब्दकोश, दैनिक प्रयोग हेतु अंग्रेजी-हिंदी नेमी टिप्पणियां तथा हिंदी संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए संदेश युक्त टेबल स्टैण्ड - 'यदि आप हिंदी में बात करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी।' - वितरित किए गए।

बैठक में मंडल कार्यालय के सभी शाखा अधिकारी, अन्य अधिकारी, मुख्य कार्यालय अधीक्षक/कार्यालय अधीक्षक तथा स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष/सदस्य-सचिव उपस्थित रहे। बैठक का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन सहायक कार्मिक अधिकारी एवं संपर्क राजभाषा अधिकारी एस.एल. खोत द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में राजभाषा विभाग के वी.बी. काडगे (वरिष्ठ अनुवादक), राजीव वलिवकर (वरिष्ठ अनुवादक), श्री शिव साहब यादव (कनिष्ठ अनुवादक) और किरण माने (कार्यालय सहायक) का विशेष योगदान रहा।

सोलापुर मंडल पर हो रहे इन आयोजनों से राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार और राजभाषा नीति के प्रभावी अनुपालन को नई गति और दिशा प्राप्त हो रही है।

सम्पादकीय

कन्याओं का पूजिये भी, आत्मसुरक्षा भी सिखाइए

22 सिंतबर रविवार से शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। नवरात्र में अधिकांश हिंदू परिवार घर में मां के कलश की स्थापना करते हैं।इन नौ दिन उपवास रखकर देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है।देवी स्परुपा कन्याओं को पूजा जाता है। उन्हें जिमाया जाता है। वस्त्रादि भेंट किए जाते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। सदियों से चली आ रही इस परम्परा में वक्त के हिसाब से अब सुधार की जरूरत है। आज जरूरत है कि हम कन्याओं को पूजे और जिमाएं ही नहीं। उन्हें शिक्षित भी करें।उन्हें आज के समय और परिस्थिति में जीने के अनुकूल बनाए। आत्मसुरक्षा भी सिखाए। उन्हें गुड टच और बेड टच की जानकारी दें। कन्याओं को आज के समाज में शान और सम्मान के साथ जीने के योग्य बनाएं। ज्यादति के खिलाफ बोलना भी बताएं। ज्यादति का मुकाबला भी करना सिखाएं।

नवरात्र देश भर में अलग -अलग रूप में मनाए जाते हैं। पूजा अर्चन की जाती है। सबका तात्पर्य यह ही है कि देवी शक्ति की पूजा कर हम उनसे अपने और समाज के कल्याण का आशीर्वाद मांगे। स्वस्थ समाज की मांग करे। ये सब कुछ सदियों से चला आ रहा है। आज समय की मांग है कि हम समय के अनुरूप पुरानी मान्यताओं से कुछ आगे बढ़े। वक्त की जरूरत के साथ अपनी मान्यताओं और सोच में परिवर्तन करें।

आज देश की देवियां ,महिलाएं, मातृशक्ति विकास के हर क्षेत्र में अपना योगदान कर रही हैं। कार - स्कूटर तो बहुत समय से चलाती रही हैं। अब ये आटो, ट्रक,ट्रेन ,मालगाड़ी भी चलाने लगीं हैं।ये प्लेन उड़ा रही हैं। अब तो सेना में जाकर बार्डर की हिफाजत भी महिलाएं कर रही हैं। आधुनिकतम लड़ाकू विमान भी उड़ा रहीं हैं। उन्हें नियंत्रित भी कर रही हैं। कभी गाना , बजना, नाचना महिलाओं की कला मानी जाती थी। उसमें उन्हें पारंगत करने के साथ- साथ पुराने समय से परिवार की बेटियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई,अनाज पिसाई,छनाई के साथ घर के कामकाज भोजन बनाने में आदि में निपुण किया जाता था। ताकि वह समय की जरूरत के हिसाब के शादी के बाद अपने परिवार को संभाल सकें। इस समय शिक्षा पर उतना जोर नही था। परिवार की जरूरतें बढ़ी तो पढ़ी -लिखी महिलाएं घर की चाहरदीवारी से निकलीं। नौकरी करने लगीं। बिजनेस में परिवार को सहयोग देने लगीं।समय बदला । महिलाएं आज शिक्षित हो सभी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं। नौकरी के लिए अकेली युवती का विदेश जाना अब आम हो गया। पैरा मिलेट्री फोर्सेज में योगदान करने के साथ आज वह सेना में आकर देश सीमाओं को सुरक्षित बनाने और शत्रु से लोहा लेने में भी लगी हैं।

समय के साथ- साथ समाज की प्राथमिकताएं भी बदलीं। नहीं बदला तो महिलाओं और युवतियों के शोषण का सिलसिला। भारतीय समाज में फैली दहेज की कुप्रथा के कारण गर्भ में ही बालिका भ्रूण मारे जाने लगे। परिवार में ही आसपास ने नाते, रिश्तेदारों और अन्यों द्वारा छुटपन से बेटियों के साथ छेड़छाड़ ,यौन शोषण चलता रहा। देश में चेतना आई ,शिक्षा का स्तर बढ़ा पर महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध कम नही हुए। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने सूचित किया कि वर्ष 2021 के प्रारंभिक आठ महीनों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की शिकायतों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय महिला आयोग को साल 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की करीब 31,000 शिकायतें मिलीं थी जो 2014 के बाद सबसे ज्यादा हैं। इनमें से आधे से ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश के थे। महिलाओं के खिलाफ अपराध की शिकायतों में 2020 की तुलना में 2021 में 30 प्रतिशत का इजाफा हुआ था। साल 2020 में कुल 23,722 शिकायतें महिला आयोग को मिली थीं।राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 30,864 शिकायतों में से, अधिकतम 11,013 सम्मान के साथ जीने के अधिकार से संबंधित थीं। घरेलू हिंसा से संबंधित 6,633 और दहेज उत्पीड़न से संबंधित 4,589 शिकायतें थीं। ये वे शिकायत हैं जो रजिस्टर होती हैं1 इससे कई गुनी शिकायत तो दर्ज ही नही होती। परिवार का सम्मान बताकर ,युवती की स्मिता की बातकर घटनांए दबाली जाती हैं।

अब तक बच्चियों को गाने - बचाना ,डांस करने के वीडियो सामने आते थे। हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें एक पिता अपनी बेटी को लाठी चलाना सिखा रहा है। इस छोटे से वीडियो को बहुत पसंद किया गया।एक और वीडियों पोपुलर हो रहा है। इसमें एक युवती अपने चेहरे पर स्कार्फ बांध रही है। एक युवक उसका स्कार्फ लेर उसे राजस्थानी पगड़ी की तरह बाधंता है। युवती के सिर पर पगड़ी बंधी देख दर्शक उसकी प्रशंसा करते हैं। आज समय की मांग है कि परिवार विशेषकर मां बेटी को बचपन से गुड टच और बैड टच बताए। इनका अंतर बताए। कहीं कुछ घर के आसपास , स्कूल में, स्कूल बस में अगर ऐसा होता है तो वह घर आकर बतांए। बेटी अब घर की देहरी के अंदर तक ही सीमित नही रह गई है। वह कार्य के लिए घर से बाहर निकल रही है। ट्रेन में, बस में अकेले सफर कर रही है। नौकरी के लिए सात समुंद पार जा रही है। ऐसे में जरूरत है उसे आत्मसुरक्षा की जानकारी देने की। जूडे-कराटे सिखाए जाएं । जरूरत है घर की प्रत्येक बेअ को आत्मसुरक्षा में निपुण करने की, ताकि वह विपरीत परिस्थिति में अपना बचाव कर सके। अगर ऐसा होगा तो छेड़छाड़ करने वाले के भय से युवती को आत्महत्या नही करनी पड़ेगी, जबकि आज इस तरह की रोज अखबारों में खबर आ रही हैं।

पिछले दिनों मुरादाबाद में से 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा ने छेड़छाड़ से परेशान होकर कीटनाशक खा कर आत्महत्याकर ली। मुंबई के विनोबा भावे नगर में चचेरे भाई के बार-बार यौन उत्पीड़न से तंग आकर 15 वर्षीय किशोरी ने आत्महत्या कर ली। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में मनचले की छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी की। इस तरह की खबर रोज अखबारों में सुर्खियां बन रही हैं। हम अपने परिवार की बेटी को ऐसे संस्कार और शिक्षा दें। उसे आत्मनिर्भर बनांए, आत्मसुरक्षा सिखाएं,ज्यादति के खिलाफ उसे आवाज उठाना भी सिखांए ताकि समाज की कन्या और समाज बेटी की खबर अखबार की सुर्खी न बने। उसके साथ ज्यादति करने का कोई हौंसला न कर सके । हाल में अच्छा यह हुआ है कि केंद्र ने इस तरह की घटनाओं के लिए पास्को एक्ट बनाया। इसमें त्वरित न्याय दिलाने की भी व्यवस्था की है, ताकि अपराधी अपराध करता डरे। जरूरत है कि पास्को एक्ट के तहत हुए निर्णयों का प्रचार -प्रसार व्यापक स्तर से किया जाए ताकि अपराधी में भय पैदा हो।

क्या 22 सितंबर से आसान हो जाएगी जिंदगी? सिर्फ सामान सस्ता होगा या नौकरियों के अवसर भी बढ़ेंगे?

इन दिनों पूरे देश की निगाहें 22 सितंबर से लागू होने वाले वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के लाभों को मुट्ठी में लेने के लिए लगी हुई हैं। जीएसटी संबंधी बड़े सुधार के एलान के बाद इस विषय पर सामने आ रही रपटों में कहा जा रहा है कि करों में कटौती आम आदमी के लिए राहत और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की दिशा में परिवर्तनकारी पहल साबित हो सकती है। मगर जीएसटी में सुधार को लेकर जागरूकता के साथ-साथ इसका ठीक से क्रियान्वयन भी जरूरी है।

जागरूकता और अधिकारियों एवं उद्यमियों-कारोबारियों के बीच सार्थक वार्ता से जहां जीएसटी संबंधी भ्रम दूर होंगे, वहीं उद्योग-व्यवसाय, विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जीएसटी सुधारों से सहजता से लाभान्वित होंगे। खास बात यह भी है कि जीएसटी सुधारों ने देश को एक तरह की आर्थिक सुरक्षा दी है, जिसकी उपयोगिता आगामी समय में किसी भी भू-राजनीतिक चुनौती और आर्थिक अनिश्चितता के कारण होने वाले प्रभावों की भरपाई के रूप में दिखाई दे सकती है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 56वीं बैठक में महंगाई से आम आदमी को राहत देने, अमेरिकी शुल्क से जूझ रहे उद्योग-कारोबार को गति देने और देश की आर्थिक रफ्तार बढ़ाने के मद्देनजर जीएसटी ढांचे तथा दरों में आमूल-चूल सुधार करने के लिए प्रभावी निर्णय लिए गए हैं। ये व्यापक सुधार नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और खासतौर से छोटे व्यापारियों के लिए काम करना आसान हो जाएगा। यदि हम देश में जीएसटी व्यवस्था से पहले लागू विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को देखें, तो पाते हैं कि देश में मूल्य वर्धित कर (वैट), सेवाकर, उत्पाद शुल्क जैसे कई अप्रत्यक्ष करों के कारण उद्योग-कारोबार कठिनाई का सामना करते रहे हैं।

एक जुलाई 2017 से देशभर में लागू जीएसटी पर विगत आठ वर्षों में व्यापक मूल्यांकन और विश्लेषण के बाद अब इसमें सरलता लाने और नए जीएसटी ढांचे के दिशानिर्देश को मंजूरी दी गई है। जीएसटी में सुधार के तीन बड़े आधार हैं। पहला, कर संरचना सुधार। इसमें कर ढांचे को और बेहतर किया गया है। दूसरा, दरों को तर्कसंगत बनाया गया, ताकि जरूरी वस्तुएं सस्ती हों तथा तीसरा, नए पंजीकरण एवं रिफंड को आसान बनाया गया है।

यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि जीएसटी के पंजीकरण से लेकर पालन की प्रक्रिया भी आसान की गई है। एक नवंबर से छोटे और कम जोखिम वाले व्यवसायों के लिए आसान जीएसटी पंजीकरण योजना शुरू करने का जो निर्णय लिया गया है, वह अत्यधिक लाभप्रद होगा। खास तौर से वैकल्पिक सरलीकृत जीएसटी पंजीकरण योजना के अंतर्गत कम जोखिम वाले छोटे उद्योग से जुड़े कारोबारी आवेदन जमा करने की तिथि से तीन कार्य दिवसों के भीतर स्वचालित आधार पर पंजीकृत हो जाएंगे।

निस्संदेह जीएसटी की नई दरें कितनी लाभप्रद होंगी, इसका अंदाज इस बात से लगा सकते हैं कि इस नए बदलाव से वर्तमान में बारह फीसद जीएसटी वाली लगभग 99 फीसद वस्तुएं अब पांच फीसद कर श्रेणी के दायरे में आ जाएंगी। जबकि अट्ठाईस फीसद कर वाली लगभग नब्बे फीसद वस्तुएं अठारह फीसद कर दायरे में आ जाएंगी। इसके अलावा रोटी-परांठे और कैंसर समेत तैंतीस जीवनरक्षक दवाओं पर अब जीएसटी नहीं लगेगा।

सभी वाहन-पुर्जों पर जीएसटी अठारह फीसद होगा। सीमेंट पर कर अब 28 फीसद से घट कर 18 फीसद हो गया है। इससे अब घर बनाने में आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। निश्चित रूप से नए बदलाव से आम आदमी से लेकर किसानों और छोटे उद्योगों के इस्तेमाल में आने वाली सैकड़ों वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी।

अगर नई जीएसटी दरों से खपत बढ़ती है, तो अतिरिक्त 52, 000 करोड़ रुपए का फायदा भी होगा, जिसमें से 26, 000 करोड़ केंद्र को और इतना ही राज्यों को मिलेगा। इसका मतलब है कि नए वित्तीय वर्ष में भी राज्यों की आमदनी बेहतर रहेगी। जीएसटी की व्यवस्था ऐसी है कि राज्यों की आमदनी थोड़े समय के लिए कम होने पर भी उन्हें नुकसान नहीं होता। चाहे जीएसटी की दरों में बदलाव किया जाए या मुआवजा शुल्क बंद हो जाए, राज्यों के पैसे सुरक्षित रहते हैं। इस व्यवस्था में यह सुनिश्चित किया जाता है कि कर सुधार के दौरान भी राज्यों के खजाने और हित पूरी तरह सुरक्षित रहें।

वर्ष 2018 और 2019 में जब जीएसटी दरों में बदलाव किया गया था, तो शुरू में राजस्व में थोड़ी गिरावट (तीन से चार फीसद) आई, लेकिन कुछ ही महीनों में राजस्व फिर से बढ़ने लगा। इसका मतलब है कि दरों में बदलाव केवल थोड़े समय के लिए असर डालता है, जबकि दीर्घकालिक स्तर पर यह फायदेमंद होता है। इससे व्यवसायों पर कर जमा करने का बोझ कम होता है।

यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि जीएसटी में सुधारों से घरेलू खपत में जोरदार तेजी आने से आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ेगी। मध्यम वर्ग उत्पादों की खरीदी पर पैसा खर्च करेगा। सरकार को भी उम्मीद है कि सालाना राजस्व नुकसान के बावजूद बाजार की गतिविधियों में तेजी आएगी और अर्थव्यवस्था को जिस तरह रफ्तार मिलेगी, उससे तात्कालिक नुकसान की सरलता से भरपाई हो जाएगी। निश्चित रूप से आम आदमी और मध्यमवर्गीय लोगों को कीमतों में राहत मिलेगी। वहीं, लोगों की क्रय शक्ति बढ़गी।

बाजार में नकदी प्रवाह भी बढ़ेगा। जो छोटे उद्योग अमेरिकी शल्क के कारण निर्यात घटने को लेकर चिंतित हैं, उन्हें घरेलू उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग से बड़ा सहारा मिलेगा। इतना ही नहीं जीएसटी घटने से औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा और और विनिर्माण क्षेत्र से लेकर सेवा क्षेत्र तक मांग का बढ़ता हुआ दायरा साफ दिखाई देगा। अनुमान है कि देश में जीएसटी घटने से करीब दो लाख करोड रुपए की खपत बढ़ेगी और निर्यात को भी नई गति मिलेगी।

मांग और उत्पादन बढ़ने से जीडीपी में भी वृद्धि होगी। रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में हाल ही में नौ सितंबर को वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजंसी मूडीज ने अपनी एक रपट में कहा है कि भारत में जीएसटी दरों में कमी किए जाने से निजी उपभोग को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक विकास की स्थिति मजबूत होगी। साथ ही इससे महंगाई में भी कमी आने की उम्मीद है।

इसी तरह वैश्विक साख निर्धारण करने वाली एजंसी 'एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग' ने कहा है कि भारत में पिछले पांच-छह वर्षों के दौरान जीएसटी में सुधार बहुत सफल साबित हुए हैं। अब इसकी दो दरें बनने से इसकी कार्यान्वयन और लेखांकन प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इससे विकास दर की ऊंचाई बढ़ेगी। पिछले दिनों वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की विकास दर के अनुमान को 6.5 फीसद से बढ़ा कर 6.9 फीसद कर दिया है। उम्मीद करें कि सरकार नई जीएसटी व्यवस्था के प्रति जागरूकता और कार्यान्वयन पर शुरुआत से ही ध्यान देगी। इन बदलावों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अधिकारियों और व्यापार जगत के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जीएसटी और कर कानूनों की सरलता से सभी लोग लाभान्वित हों तथा भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगे।

दिखावे की दौड़ में खो गई 'कम में खुश रहने की सोच', युवाओं को सादगी क्यों लग रही है बोझ?

दिखावे के दौर में कहीं न्यूनतमवाद भी है, जो एक जीवनशैली है। यह सादगी, संयम और भौतिक वस्तुओं की न्यूनतम आवश्यकता की बात करती है। यह विचारधारा कहती है कि कम चीजों में भी सच्चा सुख है और जब हम अनावश्यक वस्तुओं, लालसाओं और दिखावे से खुद को दूर करते हैं, तभी हम भीतर से पूर्ण हो पाते हैं। मगर आज की युवा पीढ़ी इस विचारधारा को अपनाने से कतरा रही है। उनके लिए न्यूनतमवाद केवल एक दार्शनिक आदर्श बनकर रह गया है, जिसे वे व्यवहार में लाना नहीं चाहते। आखिर ऐसा क्यों है?

वर्तमान समय का युवा एक नई दुनिया में जी रहा है। एक ऐसी दुनिया, जो विकल्पों से भरी हुई है। सोशल मीडिया, ई-वाणिज्य, डिजिटल कारोबार और अनगिनत ब्रांड ने युवाओं को यह विश्वास दिला दिया है कि अधिक पाना ही जीवन की उपलब्धि है। आए दिन नया फोन, नया फैशन, नया चलन- यह सब उसकी मानसिकता का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में जब कोई उसे कहता है कि 'कम में जीना सीखो', तो यह उसके लिए एक अव्यावहारिक सलाह लगती है।

जिस न्यूनतमवाद को एक समय बुद्धिजीवियों और आत्मिक संतुलन चाहने वालों ने अपनाया था, अब एक पुरानी सोच के रूप में देखा जाने लगा है। आज का युवा घूमना और अनुभव करना चाहता है, प्रयोग करना चाहता है और उन सभी चीजों का हिस्सा बनना चाहता है, जो उसकी उम्र एवं समय के साथ चल रही हैं।

डिजिटल युग में युवा हर पल एक चमकती हुई दुनिया से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी की

झलकियां उसे अपनी जिंदगी से असंतुष्ट कर देती हैं। हर किसी के पास कुछ नया, आकर्षक और आधुनिक है। ऐसे में अगर वह खुद को सीमित रखता है, तो उसे डर होता है कि वह इस दौड़ में पीछे न रह जाए। यह डर युवाओं को हर बार कुछ और पाने की दिशा में धकेलता रहता है।

इसके अलावा, आधुनिक समाज में भौतिक वस्तुएं केवल जरूरत नहीं रहीं, बल्कि 'स्टेटस सिंबल' या हैसियत के दिखावे का प्रतीक बन चुकी हैं। कौन-सी कार चलाते हैं, किस ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, कहां घूमने जाते हैं- इन सब बातों से एक व्यक्ति की कामयाबी तय होती है। ऐसे माहौल में जब एक युवा खुद को सीमित वस्तुओं तक ही बांधने की सोचता है, तो उसे लगता है कि वह अपनी पहचान को ही कमजोर कर रहा है।

उसे यह भय सताता है कि कहीं उसका सरल जीवन उसकी प्रगति में बाधा न बन जाए। न्यूनतमवाद को लेकर एक और समस्या यह भी है कि इसे अक्सर 'त्याग' या 'संकोच' के रूप में देखा जाता है। जबकि वास्तव में इसका मूल उद्देश्य संतुलन है। मगर आज की भाषा में त्याग का अर्थ अक्सर मजबूरी या गरीबी से जोड़ दिया जाता है। युवाओं को लगता है कि जब दुनिया सारी सुविधाएं दे रही है, तो वे क्यों पीछे रहें। क्यों वे उस विचार को अपनाएं, जो उन्हें कुछ न करने, न खरीदने, न चाहने की सलाह देता है? हालांकि, यह भी उतना ही सच है कि आज की युवा पीढ़ी मानसिक रूप से थकी हुई है।

तेजी से बदलती दुनिया, करिअर की दौड़, सामाजिक दबाव और लगातार खुद को साबित करने की जरूरत ने उन्हें भीतर से असंतुलित कर दिया है। यही कारण है कि अब कई युवा 'डिजिटल डिटाक्स' यानी तकनीक से दूरी, ध्यान और एकाग्रता, 'सोलो ट्रैवल' यानी अकेले पर्यटन करना और टिकाऊ जीवनशैली जैसे विकल्पों की ओर मुड़ रहे हैं। वे सादगी की ओर लौटना तो चाहते हैं, लेकिन बिना 'त्याग' की भावना के। उन्हें एक ऐसी जीवनशैली चाहिए, जो उन्हें 'कम में भी ज्यादा' का अनुभव दे, पर वह मजबूरी न लगे।

न्यूनतमवाद को लेकर यह बदलाव भी ध्यान देने योग्य है कि अब इसका स्वरूप पारंपरिक नहीं रह गया है। आज के युवा 'न्यूनतम' का अर्थ केवल वस्तुओं से नहीं, बल्कि समय, ऊर्जा और भावनाओं की दिशा से भी जोड़ने लगे हैं। वे चाहते हैं कि उनके पास कम रिश्ते हों, पर सच्चे हों; कम काम हो, पर सार्थक हो; कम शोर हो, पर भीतर की शांति हो।

मगर ये सब तभी संभव होगा जब न्यूनतमवाद को एक जटिल जीवनशैली के रूप में प्रस्तुत न कर, मुक्त जीवन के रूप में दिखाया जाए। अगर समाज, शिक्षा और मीडिया इसे त्याग या अभाव के रूप में दिखाना बंद करें और इसकी प्रस्तुति को अधिक सकारात्मक, आकर्षक और व्यावहारिक बनाएं, तो शायद युवा भी इसे अपनाने में रुचि लें। जब तक यह विचार एक पुराने युग की सोच के रूप में प्रस्तुत होता रहेगा, तब तक यह युवा पीढ़ी के मन को छू नहीं पाएगा।

युवा किसी भी विचारधारा से डरते नहीं हैं, पर वे उसमें अपने जीवन का अर्थ देखना चाहते हैं। उन्हें समझाना होगा कि न्यूनतमवाद केवल वस्तुओं को त्यागने की बात नहीं करता, बल्कि यह उस मानसिक स्वतंत्रता की बात करता है जहां इंसान अनावश्यक से खुद को मुक्त कर पाता है। जब वे समझेंगे कि कम में भी बहुत कुछ होता है- समय, शांति, रिश्ते, ऊर्जा और आत्म-संतोष, तब वे इस दर्शन को अपनाने के लिए भी तैयार हो सकते हैं।

दरअसल, यह कहना गलत नहीं होगा कि आज के युवा न्यूनतमवाद को पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उन्हें दुनिया से काट देगा। पर सच्चाई यह है कि यह दर्शन उन्हें दुनिया से जुड़ने का एक गहरा, शांत और संतुलित तरीका दे सकता है। जरूरत है इस सोच को सही भाषा, सही माध्यम और सही संदर्भ में प्रस्तुत करने की। तभी युवा इसे अपनाने की ओर आकर्षित होंगे, और शायद उस सच्ची खुशी को पा सकें जो चीजों के ढेर में नहीं, बल्कि सादगी की गहराई में छिपी होती है।

हरियाणा में तबादला संकटः शिक्षकों की उम्मीदें टूटीं

'अप्रैल से इंतज़ार, तबादले अभी भी अधर में; मॉडल स्कूलों के नतीजे स्थगित, नई नीति अधूरी'

- डॉ. सत्यवान सौरभ

हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था इस समय गहरे असमंजस और गतिरोध के दौर से गुज़र रही है। हजारों शिक्षक अप्रैल से अपने तबादलों का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन नतीजा यह है कि महीनों बीत जाने के बाद भी कोई ठोस प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। सरकार और विभाग बार-बार आश्वासन दे रहे हैं कि तबादला अभियान जल्द ही शुरू होगा, लेकिन हकीकत यह है कि आज तक न तो मॉडल स्कूलों के नतीजे घोषित हुए हैं और न ही नई तबादला नीति लागू हुई है। नतीजतन, शिक्षकों का असंतोष और धैर्य जवाब देता दिख रहा है।

हरियाणा में शिक्षकों के तबादले अप्रैल में होने थे, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। सरकार ने शुरू में कहा था कि पहले मॉडल स्कूलों के नतीजे घोषित किए जाएँगे और फिर उसके आधार पर तबादला अभियान चलाया जाएगा। हालाँकि, तब से महीनों बीत चुके हैं, और ये नतीजे जारी नहीं हुए हैं। शिक्षकों को नई तबादला नीति का वादा करके अधर में लटकाए रखा जा रहा है, जबकि वह नीति अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। इस देरी ने हजारों शिक्षकों को भ्रमित और निराश कर दिया है, क्योंकि कई शिक्षक कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और समय पर तबादलों के ज़रिए राहत की उम्मीद कर रहे थे। लगातार किए जा रहे वादों और अधूरी तैयारियों ने उनके धैर्य की परीक्षा ले ली है। अब, यह ज़रूरी है कि सरकार मॉडल स्कूल के नतीजे तुरंत घोषित करे, नई नीति स्पष्ट करे और पूरी पारदर्शिता के साथ स्थानांतरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाए।

स्थानांतरण किसी भी शिक्षक के लिए सिर्फ़ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है। यह उनके निजी जीवन, पारिवारिक परिस्थितियों और पेशेवर संतुष्टि से गहराई से जुड़ा होता है। जो शिक्षक वर्षों से एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, वे बदलाव की उम्मीद करते हैं, जबकि दूरदराज के इलाकों में तैनात शिक्षक अपने परिवार और बच्चों से जुड़ने के लिए तरसते हैं। जब ये उम्मीदें

लगातार पूरी नहीं होतीं, तो इसका असर उनके मनोबल और प्रदर्शन, दोनों पर पड़ता है।

अप्रैल में, सरकार ने दावा किया था कि मॉडल स्कूल के नतीजे पहले घोषित किए जाएँगे और स्थानांतरण प्रक्रिया उनके मार्गदर्शन में होगी। हालाँकि, ये नतीजे महीनों से लंबित हैं। इसके साथ ही, सरकार ने प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए एक नई स्थानांतरण नीति की घोषणा की। यह घोषणा निश्चित रूप से आकर्षक लग रही थी, लेकिन जब यह नीति महीनों तक अधर में लटकी रही और शिक्षकों को इसकी कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं दिखाई दी, तो यह सिर्फ़ समय काटने का एक बहाना प्रतीत होता है। यह पूरी देरी शिक्षा व्यवस्था पर सीधा असर डाल रही है। जहाँ कुछ स्कूलों में ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षक हैं, वहीं कई ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में वर्षों से पद खाली पड़े हैं। नतीजतन, बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है और असमानता बढ़ रही है। शिक्षा सुधार के प्रतीक के रूप में प्रचारित मॉडल स्कूल परियोजना के नतीजे न आना सरकार की गंभीरता पर सवाल खड़े करता है।

शिक्षकों ने धैर्य बनाए रखा है, लेकिन अब उनकी आवाज़ें तेज़ हो रही हैं। यूनियनें और संगठन पूछ रहे हैं कि जब पुरानी नीति के तहत यह प्रक्रिया पूरी हो सकती थी, तो इसे क्यों रोका गया। क्या नई नीति का हवाला देकर शिक्षकों को महीनों तक असमंजस में रखना राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी को नहीं दर्शाता? शिक्षकों का मानना ??है कि अगर सरकार वाकई पारदर्शिता चाहती है, तो उसे नीति को सार्वजनिक करना चाहिए। अगर वह तैयार नहीं है, तो उसे पुरानी नीति के तहत प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, ताकि शिक्षकों को कम से कम कुछ राहत तो मिल सके।

हरियाणा जैसे राज्य में, जहाँ शिक्षा सुधार और मॉडल स्कूलों पर व्यापक रूप से चर्चा हुई है, आज स्थिति ऐसी है कि शिक्षक अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित हैं। यह केवल शिक्षकों का संकट नहीं है, बल्कि छात्रों और पूरी शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न है। अगर शिक्षक असंतुष्ट और निराश रहेंगे, तो वे बच्चों को पूरी लगन से कैसे पढ़ा पाएँगे?

अब जबकि सितंबर का महीना खत्म होने वाला है, सरकार को और देर नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले, शिक्षकों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए मॉडल स्कूलों के परिणाम घोषित करना ज़रूरी है। इसके बाद, नई नीति को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, और यदि यह अधूरी है, तो पुरानी नीति के तहत स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। यह भी ज़रूरी है कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल और समयबद्ध तरीके से हो, ताकि किसी भी संभावित पक्षपात या पक्षपात को दूर किया जा सके।

अंततः, यह समझना होगा कि शिक्षक केवल सरकारी कर्मचारी नहीं, बल्कि समाज की रीढ़ हैं। उन्हें अनिश्चितता में रखना और महीनों तक प्रतीक्षा में रखना उनके साथ अन्याय है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अगर सरकार वास्तव में शिक्षा में सुधार चाहती है, तो उसे तत्काल, ठोस और पारदर्शी कदम उठाने होंगे। हरियाणा के शिक्षकों का धैर्य जवाब दे रहा है, और अब समय आ गया है कि सरकार वादों और घोषणाओं से आगे बढ़कर वास्तविक कार्रवाई करे। यही एकमात्र रास्ता है जो शिक्षकों को न्याय दिलाएगा और हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को संतुलन और मज़बूती प्रदान करेगा।

मा0 प्रभारी मंत्री ने नेक्स्ट-जेन जीएसटी, जन-प्रथम सुधार पर प्रसे वार्ता कर दी व्यापक जानकारी

इस जीएसटी सुधार से मध्यम वर्ग के जीवन में सुगमता आयेगी और वे अधिक सशक्त होगें-ए0के0शर्मा

भदोही। मा0 मंत्री नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय योजनाएं एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा, स्त्रोत उ0प्र0 व जनपद प्रभारी मंत्री ए. के. शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में मा0 सांसद डॉ0 विनोद बिन्द, मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरूद्ध त्रिपाठी, मा0 विधायक औराई दीनानाथ भाष्कर, ज्ञानपुर विपुल दूबे, मा0 जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा के उपस्थिति में जीएसटी सुधार कर प्रेस कॉन्फ्रेस के माध्यम से इसके जनहितार्थ आयामों पर बल दिया। उन्होंने बताया कि मा0 प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए रणनीतिक रूप से प्रभावशाली बदलाव किये और उन्हें सफलता पूर्वक लागू किया। जिससे उनके जीवन में सुगमता आयी और वे अब अधिक सशक्त हो गये है। नेक्स्ट-जेन जीएसटी जन-प्रथम सुधारों में मिल का पत्थर साबित होगा। इससे सुलभ दाम, हर परिवार की मुस्काल बढेगी, रोजमर्रा की जरूरतों पर रोजाना बचत होगा।

मा0 प्रभारी मंत्री जी ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में नेक्स्ट-जेन जीएसटी सुधारों के लिए 3 सितम्बर 2025 को 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी सुधारों के निर्णय लिए गए। यह 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है। इन सुधारों के तहत 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की सरल दो-दर संरचना

लागू की गई है, जबकि विलासिता और लग्जरी सामानों पर 40 प्रतिशत की दर रखी गई है। इससे पारदर्शिता, न्यायसंगत व्यवस्था और कर पालन में आसानी की पुरानी मांगों को पूरा किया गया है। ये सुधार नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगे। यह केवल आर्थिक कदम नहीं, बल्कि देश के लिए दिवाली का तोहफ़ा हैं, इससे करोड़ों परिवारों की बचत सीधे उनके हाथों में जाएगी। जैसे दीपावली पर दीपक घरों को रोशन करते हैं, वैसे ही ये सुधार घरों के खर्च कम करेंगे, किसानों को सशक्त बनाएंगे और कारोबार को गति देंगे, जिससे पूरे भारत में समृद्धि फैलेगी।

जीएसटी सुधार के मुख्य बिन्दु निम्न हैं-दो-दरों की सरलताः अब पुरानी चार-स्तरीय व्यवस्था हटाकर सिर्फ 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दरें रखी गई हैं। इससे भ्रम, कानूनी झंझट और टैक्स भरने की मुश्किलें कम होंगी। जनता को राहतः दूध, पनीर, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, साइकिल और बच्चों के सामान जैसे जरूरी घरेलू सामान पर अब सिर्फ 5ः या शून्य कर लगेगा। इससे रोजमर्रा के खर्च कम होंगे। किसानों को बढ़ावाः ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक और सिंचाई उपकरण पर कर घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे खेती की लागत कम होगी और ग्रामीण भारत को सीधा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य क्रांतिः व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया है। दवाइयों, ऑक्सीजन और जांच किट पर कर में बड़ी कटौती की गई है ताकि इलाज सभी के लिए सस्ता हो सके। गाड़ियों और वाहनों में भारी छूटः गाड़ियों और बाइक पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी है-यानी पूरे 10 प्रतिशत की कटौती-जिससे वाहन खरीददारों को आराम मिलेगा और त्योहारों के समय मांग बढ़ेगी। शिक्षा हुई सस्तीः कॉपियों, पेंसिल, नक्शों और अन्य ज़रूरी छात्र सामग्री पर अब कोई कर नहीं लगेगा। लग्जरी पर ज्यादा कर प्रतिशत विलासिता की वस्तुएं (जैसे तंबाकू, पान मसाला) और लग्जरी सामान (जैसे कसीनो, एसयूवी, यॉट) पर अब 40 प्रतिशत कर लगाया गया है। इससे आम लोगो पर बोझ घटेगा। व्यापार में आसानीः सरल रजिस्ट्रेशन, तेज रिफंड (90 प्रतिशत ऑटो-अप्रूव) और रिस्क-आधारित कंप्लायंस से एमएसएमई, निर्यातकों और श्रम प्रधान क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी। वित्तीय सतर्कताः तंबाकू पर सेस तब तक जारी रहेगा जब तक मुआवजे के ऋण चुकते नहीं है, जिससे राजस्व प्रबंधन जिम्मेदारी से होगा। आर्थिक प्रभाव-मजबूत राजस्व वृद्धिः दरें कम होने के बावजूद, वित्त वर्ष 25 में जीएसटी संग्रह 22.08 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। केवल अप्रैल-अगस्त 2025 में ही 10.04 लाख करोड़ का संग्रह हुआ, जो विकास और बेहतर अनुपालन का प्रमाण है। कर आधार का विस्तारः पंजीकृत करदाताओं की संख्या 2017 में 65 लाख से बढ़कर 2025 में 1.51 करोड़ से अधिक हो गई, जिससे लाखों लोग औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल हुए। खपत बढ़ेगीः आम इस्तेमाल की वस्तुओं पर कम कर से घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, खासकर मध्यम और निम्न आय वाले वर्ग में। जीडीपी में बढ़ोतरीः मजबूत खपत, निवेश और कर संग्रह के जरिए जीडीपी वृद्धि में अनुमानित 0.2-0.3 प्रतिशत का योगदान मिलेगा। पूर्वानुमानः स्थिर और पारदर्शी दो-दर संरचना लंबे समय के व्यापार और निवेश की योजना में भरोसा बढ़ाती है। 2025 के सुधार "जीवन में आसानी, व्यापार में आसानी" के विजन को दर्शाते हैं। सामान्य नागरिकों पर कर का बोझ कम करके, किसानों को सशक्त बनाकर, विनिर्माण को बढ़ावा देकर और लग्जरी तथा विलासिता वस्तुओं पर भार बढ़ाकर, एनडीए सरकार ने समावेशी विकास और वित्तीय जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोबारा साबित की है।

जय हिंद कॉलेज में 'वॉयज 2025' में आईआरसीटीसी पश्चिम क्षेत्र की सहभागिता

जय हिंद कॉलेज, मुंबई के बी.वोक विभाग ने 17 से 19 सितम्बर 2025 तक अपने वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम 'वॉयज 2025' का सफल आयोजन किया, जिसका विषय 'सस्टेनेबिलिटी एंड टूरिज़्म' (सततता और पर्यटन) था। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड पश्चिम क्षेत्र के महाप्रबंधक श्री गौरव झा ने विशिष्ट वक्ता के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई। अपने संबोधन में श्री झा ने पर्यटन क्षेत्र में सततता के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला और आईआरसीटीसी द्वारा देशभर में पर्यावरण-अनुकूल और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु किए जा रहे प्रयासों व पहलुओं को साझा किया।

उन्होंने उल्लेख किया कि माननीय रेल मंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और आईआरसीटीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री संजय कुमार जैन देव मार्गदर्शन में आईआरसीटीसी ने कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की हैं, जैसे–जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण-अनुकूल टूर पैकेज, डिजिटल टिकटिंग, स्थानीय संस्कृति और धरोहर का संवर्धन–जो भारत की सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं।

यह सत्र छात्रों के लिए अत्यंत प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धक सिद्ध हुआ, जिसमें उन्हें पर्यटन प्रथाओं में सततता को शामिल करने के व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी मिली और इस क्षेत्र में विविध करियर अवसरों की संभावनाओं से भी अवगत कराया गया।

कार्यक्रम में अन्य गणमान्य अतिथियों की भी गरिमामयी उपस्थिति रही, जिनमें श्री मोहम्मद फारूक, उप महानिदेशक एवं क्षेत्रीय निदेशक, पर्यटन मंत्रालय; श्री निलेश रमेश घाटणे, प्रबंध निदेशक, एमटीडीसी; तथा श्री अजय प्रकाश, अध्यक्ष, ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। अन्य प्रतिष्ठित वक्ताओं ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

उत्तर रेलवे भारत स्काउट्स एवं गाइड्स हेडक्वार्टर जिला की कार्यकारिणी एवं परिषद् बैठक का सफल आयोजन

नई दिल्ली। उत्तर रेलवे भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, हेडक्वार्टर जिला द्वारा जिला कार्यकारिणी एवं परिषद् बैठक तथा स्काउट गाइड्स कोटा नियुक्त सदस्यों की बैठक का सफल आयोजन आज उत्तर रेलवे मुख्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली में गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ।

कार्यक्रम का शुभारंभ सामूहिक प्रार्थना से हुआ, जिसके पश्चात सभी सदस्यों का परिचय और स्कार्फ सेरेमनी अत्यंत अनुशासित रूप से सम्पन्न हुई। बैठक में जिला सचिव श्री देवेंद्र द्वारा माहवार वार्षिकी रिपोर्ट एवं गत वर्ष की गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। जिला कोषाध्यक्ष श्री प्रदीप कलसी द्वारा पिछले वर्ष और आगामी वर्ष के वित्तीय लेखा-जोखा का पारदर्शी विवरण दिया गया।

जिला ऑर्गनाइजिंग कमिश्नर (स्काउट) श्री विष्णु भगवान ने रिक्त पदों की नियुक्ति और समस्त पदों की समीक्षा पर सारगर्भित चर्चा की। जिला ट्रेनिंग कमिश्नर (गाइड) श्रीमती अनीता पाठक ने चालू वर्ष की योजनाओं पर अपने विचार रखे। जिले के सभी ग्रुप लीडर्स द्वारा अपने-अपने ग्रुप की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। संयुक्त सचिव श्रीमती निवेदिता एवं श्री शक्ति ने हेडक्वार्टर जिला की वार्षिक गतिविधियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।

बैठक में सर्वसम्मति से श्रीमती सपना दत्ता (राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त) - जिला ऑर्गनाइजिंग कमिश्नर/गाइड, श्री अनीश गुप्ता (हिमालय वुड बैज प्राप्त) - जिला ट्रेनिंग कमिश्नर/स्काउट, श्री शक्ति सिंह (राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त) - असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, श्री प्रवेश कुमार - असिस्टेंट क्वार्टर मास्टर, श्री धर्मेन्द्र कुमार - डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग काउन्सलर के महत्वपूर्ण पदों पर नव निर्वाचित सदस्य मनोनीत किए गए।

बैठक की कार्यवाही का संचालन सहायक जिला आयुक्त/गाइड एवं वरिष्ठ एस एंड एओ/उत्तर रेलवे श्रीमती हेमलता के कुशल नेतृत्व में सम्पन्न हुआ। बैठक की अध्यक्षता जिला मुख्य आयुक्त/मुख्यालय एवं मुख्य कार्मिक अधिकारी / सामान्य श्रीमती हर्षा दास ने की। इस अवसर पर उपाध्यक्ष एवं मुख्य कार्मिक अधिकारी/आई आर श्री राजीव बजाज, जिला आयुक्त/गाइड एवं उप-मुख्य कार्मिक अधिकारी/आर, उत्तर रेलवे श्रीमती मानसी वर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

बैठक के दौरान संगठनात्मक सुदृढ़ता, प्रशिक्षण, सांख्यिकीय व प्रशासनिक विषयों पर गहन चर्चा हुई। आगामी वर्ष की योजनाओं को अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने हेतु ठोस रणनीति पर सहमति बनी। सभी अधिकारियों एवं सदस्यों की सक्रिय भागीदारी और सामूहिक सहयोग से यह बैठक अत्यंत अनुशासित, सफल और सार्थक सिद्ध हुई। इस अवसर पर जिला क्वार्टर मास्टर श्री संजय इस्सर, सहायक जिला सचिव श्री कमल किशोर (जलंधर), श्रीमती आरती वर्मा, श्रीमती रोज़ी सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे।

पीस कमेटी के साथ आगामी त्यौहारों को सकुशल एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु डीएम व एसपी की अध्यक्षता में हुई बैठक

आगामी शारदीय नवरात्र, दशहरा, रामलीला आदि त्यौहार/आयोजन परम्परागत ढ़ग से शान्तिपूर्ण व सौहार्द वातावरण में मनाये-जिलाधिकारी

भदोही ।जिलाधिकारी शैलेष कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक की संयुक्त अध्यक्षता में आगामी त्यौहार शारदीय नवरात्रि, दुर्गापूजा/दशहरा, श्री रामलीला, दीपावली, गोबर्धन पूजा, छठ पूजा आदि की तैयारियों के दृष्टिगत आयोजको, पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, जनता जनार्दन, अधिकारियों के साथ पीस कमेटी बैठक का आयोजन कलेक्टेट्ट सभागार में किया गया।

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने पीस कमेटी में आयोजको, पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, जनता जनार्दन से परिचय प्राप्त करते हुए उनके समस्याओं व सुझावों से अवगत हुए। अधिकारी द्वय द्वारा उक्त त्यौहारों को सकुशल व शान्तिपूर्ण ढ़ग से सम्पन्न कराने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग, अधिशासी अधिकारी नगर निकाय, थानाध्यक्ष को निर्देशित करते हुए कहा कि रामलीला आयोजको, दुर्गापूजा पण्डाल व्यवस्थापकों, पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए आयोजन स्थल व रूट पर पैदल भ्रमण करते हुए सभी आवश्यक बिन्दुओं को नोट कर उसका तत्काल निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि परम्परागत जो आयोजन जिस रूप में अनवरत चले आ रहे है उसी रूप में होगें। किसी भी नई परम्परा/परिपार्टी की शुरूवात नही होगी। उन्होंने गंगा जमुनी तहजीब के प्रवाहक भदोहीवासियों से सभी पर आपसी प्रेम सौहार्द व भाई

चारे के साथ मनाने की अपील की।

जिलाधिकारी ने सभी पूजा पण्डाल आयोजको/व्यवस्थापकों को स्पष्ट निर्देशित किया कि पण्डाल बनाने में कही भी प्लास्टिक, थर्माकोल, पोलिथीन, चमकीली पन्नी, या जल्द आग पकड़ने वाली किसी भी समाग्री का प्रयोग किसी भी कीमत पर नही किया जायेगा। भीड़ के दृष्टिगत प्रवेश व निकासी द्वार अलग-अलग बनाये। फायर सेफ्टी के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं को अपनाये।

पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि जनपद के सभी रामलीला कमेटियों व दुर्गापूजा पण्डाल आयोजको को आयोजन हेतु अनुमति पत्र लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत पुलिस व प्रशासनिक स्तर पर की गयी तैयारियों व सुरक्षा व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में सख्त निर्देश दिए। कोई भी पूजा पण्डाल या धार्मिक आयोजन सर्वाजनिक मार्ग बाधित करके न हो, सर्वाजनिक मार्ग बाधित होने की दिशा में पण्डाल को थोडा इधर-उधर शिफ्ट कर लिया जाए, जिससे आने वाले दर्शनार्थियों को अवागमन के दृष्टिगत कोई अवरोध न पैदा हो। बारिश के दृष्टिगत पूजा पण्डाल के ऊपर वाटर शेड, विद्युत वायरिंग खुला न हो, पण्डाल के उपर विद्युत तार न हो, पण्डाल के पीछे विद्युत प्रकाश व पानी का ड्रम रखना सुनिश्चित करें। आयोजन स्थलों पर दर्शनार्थियों के आने-जाने का अलग-अलग बैरिकेटिंग हो, हो सके तो महिलाओं के आने जाने के लिए एक अलग क्लोजर की व्यवस्था हो। आयोजक व वॉलेटियर्स आई कार्ड अवश्य पहने, हो सके तो एक अलग डेड्रस कोड पहने जिससे दर्शनार्थियों को कोई समस्या होने पर वालेटियर्स को तत्काल बता सके।

जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी व पुलिस उपाधीक्षक को निर्देशित किया कि विगत वर्षो में आयोजन स्थलों मार्गो, मूर्ति रखने, रामलीला मंचन करने के सन्दर्भ में कोई विवाद हुआ हो तो उसको रोड भ्रमण करते हुए प्रबुद्धजनों के साथ आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने भदोहीवासियों को भरोसा दिलाया कि प्रशासन व पुलिस आपके सहयोग के लिए तत्पर है। उन्होंने जनपद के सभी डीजे संचालकों को निर्देशित किया कि निर्धारित ध्वनि सीमा तक ही डीजे साउण्ड का प्रयोग करें। नियमों का उल्लघन करने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।

अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 कुवर वीरेन्द्र मौर्य एवं मुख्य विकास अधिकारी बाल गोबिन्द शुक्ल ने दुर्गापूजा आयोजको को मा0 सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों से अवगत करते हुए बताया कि कोई भी मूर्ति विसर्जन नदी में न होकर चिन्हित तालाब या नहर में ही सुनिश्चित करें। विसर्जन के समय विद्युत तारो से घटना के सुरक्षा के दृष्टिगत बिजली विभाग व अधिशासी अधिकारी कार्यालय के एक-एक कर्मचारी प्रत्येक थानों से सम्बन्धित रहकर सकुशल शान्तिपूर्ण सम्पन्न करायेंगे।

पुलिस अधीक्षक एवं अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल द्वारा आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत रामलीला मंचन, दूर्गापूजन पण्डाल, विजयदशमी त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराने के दृष्टिगत सभी आवश्यक बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए आयोजको को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि त्यौहारों में असमाजिक व अराजकता फैलाने वाले तत्वों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। जनपद के सभी संवेदनशील स्थलों एवं मिश्रित बस्तियों में लगातार मॉनिटरिंग करते हुए अनवरत संवाद करने का निर्देश दिए। किसी भी सम्भावित स्थितियों की संज्ञानता में तत्काल उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

पीस कमेटी बैठक में पूजा पण्डाल, आयोजकों/व्यवस्थापकों, पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, जनता जनार्दन ने आयोजन विषयक समस्या व सुझाव को इगिंत किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, आयोजको सहित, समस्त उप जिलाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, समस्त अधिशासी अधिकारी, व सम्बन्धित जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित रहें।

इफको नैनो उर्वरक जागरूकता अभियान के अंतर्गत विकास खंड स्तरीय कृषक गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन

भदोही । जनपद भदोही में विकास खंड औराई के ग्राम पंचायत उपरौठ में नैनो उर्वरकों पर आधारित विकास खंड स्तरीय कृषक गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया । कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अध्यक्ष सह वरिष्ठ वैज्ञानिक,कृषि विज्ञान केंद्र, बेजवां भदोही डॉ. विश्वेंदु द्विवेदी थे ।

कार्यक्रम में ङकृषि विज्ञान केंद्र, बेजवां भदोहीङ से ङमृदा वैज्ञानिक ताराचंद बैरवाङ एवं नरथुआ केंद्र प्रभारी राजेंद्र जायसवाल थे । क्षेत्र अधिकारी इफको भदोही विमल कुमार जायसवाल द्वारा किसानो को किसानो को नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया प्लस के प्रयोग विधि एवं लाभ के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई । नैनो डीएपी के 5 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम की दर से बीज शोधन एवं 5 मिलीलीटर प्रति लीटर के दर से जड़ शोधन करने के बाद आधा घंटा सुखाए उसके बाद बुवाई/रोपाई कर दे एवं जब फसल में पत्तियां आ जाए तो नैनो यूरिया प्लस या नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया प्लस का एक साथ 4 मिलीलीटर / लीटर के दर से पानी में घोल बनाकर छिड़काव करे। द्वितीय यूरिया टापड्रेसिंग में सभी किसान भाई दानेदार यूरिया के स्थान पर नैनो यूरिया का छिड़काव पत्तियों पर करे ।नैनो उर्वरकों के प्रयोग से कृषकों के लागत

में भी कमी आएगी साथ ही यूरिया एवं डीएपी के अत्याधिक प्रयोग से जल,मृदा एवं पर्यावरण को होने वाले नुकसान से भी अवगत कराया गया ।

नैनो डीएपी से बीज शोधित कर बुवाई करे, लागत में आयेगी कमी

आगामी रबी सीजनङ में सभी किसान भाई मुख्य फसलों गेहूं,सरसों, आलू, चना ,मटरङ में नैनो डीएपी से बीज शोधित कर बुवाई करे एवं दानेदार डीएपी की मात्रा आधी प्रयोग करे ।नैनो डीएपी 500 मिलीलीटर की बोतल से 100 किलोग्राम बीज को शोधित कर सकते है एवं मात्र 600 रूपये की है जो कि दानेदार डीएपी से काफी सस्ता है। नैनो डीएपी के प्रयोग से लागत में कमी आएगी साथ ही उत्पादन के साथ उत्पाद की गुणवत्ता भी बढ़ती है।

किसानो को सागरिका, लिक्विड कंसोर्टिया, नैनो जिंक एवं जल विलय उर्वरक के बारे में भी जानकारी दी गई।

कृषि विज्ञान केंद्र वरिष्ठ वैज्ञानिक सह अध्यक्ष द्वारा सभी वृषकों को रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करते हुए नैनो डीएपी से बीज शोधित कर बुवाई करने एवं पत्तियां आने पर नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया प्लस का पत्तियों पर छिड़काव करने से पैदावार बढ़ती है साथ ही नैनो उर्वरकों के प्रयोग से लागत में भी कमी आती है ।

मृदा वैज्ञानिक द्वारा कृषकों को मृदा नमूना लेने के विधि की जानकारी दी गई साथ ही संतुलित मात्रा में उर्वरक उपयोग के साथ नैनो तकनीक पर आधारित नैनो यूरिया प्लस एवं नैनो डीएपी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया गया एवं दानेदार उर्वरकों पर भारत सरकार द्वारा दी जा रही भारी भरकम सब्सिडी से भी अवगत कराया गया । ङसभी कृषकों को नैनो डीएपी से बीज शोधित कर बुवाई करने के लिए प्रोत्साहित कियाङ । ङनैनो डीएपी से शोधन कर बुवाई करने पर बीजों का जमाव अच्छा होने के साथ जड़ो का विकास भी अच्छा होता हैङ और उत्पाद की गुणवत्ता भी बढ़ती है।

कार्यक्रम में एसएफए हॉटस्पॉट विकास यादव, प्रगतिशील किसान ब्रजभूषण पाण्डेय,महेंद्र सहित 100 से अधिक किसानो ने प्रतिभाग किया।

थाना भदोही पुलिस द्वारा फर्जी कम्पनी स्थापित कर षडयंत्र के तहत कूटरचित दस्तावेज तैयार कर रुपयो की ठगी करने का 5,000/- इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

भदोही । जनपद में हो रहें धोखाधड़ी/ठगी जैसे अपराध की रोकथाम हेतु अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में एवं श्री शुभम अग्रवाल अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में पंजीकृत अभियोगों को अभियान के तहत साक्ष्य संकलन एकत्रित कर सफल अनावरण हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 290/21 धारा 419/420/467/468/471/406/120 बी आईपीसी वादी मुकदमा श्री नेमलाल पुत्र स्व0 रामधनी प्रजापति नि0 जगापुर थाना जनपद भदोही के साथ अभियुक्त द्वारा फर्जी कम्पनी स्थापित कर षडयंत्र के तहत कूटरचित दस्तावेज तैयार कर एजेन्ट के माध्यम से कम्पनी पर पैसा जमा करा लेना एवं कम्पनी बंद करके भाग जाना व पैसा वापस न करने के सम्बन्ध में था। मुकदमा उपरोक्त में दौराने विवेचना अभियुक्त संतोष कुमार पाण्डेय पुत्र क्षमाकान्त पाण्डेय निवासी नहोरा परसाईपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर का नाम प्रकाश में आया जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ?5,000/- इनाम घोषित किया गया था। आज दिनांक 20.09.2025 को समय 14.00 बजे नेश्नल तिराहा से गिरफ्तार करके मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिमाण्ड बनवाकर जेल भेजा गया है।

अपराध का तरीका :-

संतोष कुमार पाण्डेय पुत्र क्षमाकान्त पाण्डेय निवासी नहोरा परसाईपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर द्वारा कंसरायपुर में रहकर फर्जी कम्पनी स्थापित कर षडयंत्र के तहत कूटरचित दस्तावेज तैयार कर एजेन्ट के माध्यम से कम्पनी पर पैसा जमा कराकर कम्पनी बंद करके पैसे लेकर भाग जाना।

सीधे-साधे समान्य दुकानदारों को साजिश व षड्यन्त्र रचकर क्यूआर कोड साउंड शुल्क माफ कराने का लालच देकर अपने जाल में फंसाकर रुपए ठगी करने के 02 अन्तर्राज्यीय अभियुक्त गिरफ्तार

भदोही। साइबर थाना जनपद भदोही पर आवेदक राहुल कुमार पुत्र राधेश्याम गौतम निवासी हरिकरनपुर थाना दुर्गागंज जनपद भदोही के अर्जुनपुर मोड़ पर परचून व टी स्टाल की दुकान पर दिनांक 11.09.2025 को समय लगभग 05.15 बजें मोटरसाइकिल सवार 02 व्यक्तियों द्वारा पेटीएम का मासिक शुल्क माफ करने का लालच देकर धोखाधड़ी कर ?21000/--फ्रॉड/ठगी करने के सम्बन्ध में साइबर क्राइम थाना भदोही पर मु0अ0स0 40/2025 धारा 318(4) बीएनएस एवं 66डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित की गई।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी का विवरणः-

अभिमन्यु मांगलिक ,पुलिस अधीक्षक भदोही निर्देशन में एवं शुभम अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में अपराधों के रोकथाम व पंजीकृत अभियोगों से सम्बंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देश के क्रम में आज दिनाक 20.09.25 को प्रभारी निरीक्षक बृजेश सिंह मय हमराह पुलिस थाना साईबर थाना के साथ दिनांक 11.09.2025 को अर्जुनपुर मोड़ के पास राहुल कुमार के परचून की दुकान से फ्राड करने के संबंध मे पंजीकृत मु0अ0सं0 40/2025 धारा 318(4) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट से संबंधित अभियुक्तगण एक मोटरसाइकिल से वाराणसी की तरफ से औराई होते हुए मिर्जापुर की तरफ जाने वाले है इस सूचना पर आने वाले व्यक्तियो का इंतजार करते समय एक मोटरसाइकिल से 02 व्यक्ति आते हुए जिनको हिरासत में लिया गया । पकड़े गये व्यक्तियों से उनका नाम पता पूछा गया तो मोटरसाइकिल चला रहे व्यक्ति ने अपना नाम विशाल ओझा पुत्र सचेन्द्र कुमार ओझा निवासी निराला नगर लेन नं0 -06 महमूरगंज थाना-महमूरगंज वाराणसी उम्र लगभग 30 वर्ष व दूसरे ने अपना नाम प्रकाश पाठक पुत्र विजय कुमार पाठक निवासी न्यू एरिया डेहरी पाठक भवन आनसोन थाना डेहरी जिला रोहतास बिहार उम्र लगभग 28 वर्ष बताया । पकड़े गये दोनो व्यक्तियो को उनका अपराध साइबर क्राइम थाना भदोही पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0- 40/2025 धारा 314(4) 66डी आईटी एक्ट का अनावरण करते हुए अन्तर्गत धारा 338,336(3),340(2) बीएनएस की बढ़ोतरी कर गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ का विवरणः पूछताछ में दोनो अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग आनलाइन बैंक खाता खुलवाते है । जिसमे केवाईसी वेरीफिकेशन नही होता है केवल फेस वेरिफिकेशन होता है । जिसके कारण मेरा कोई दस्तावेज वहाँ जमा नही होता फिर उसी बैंक खाते मे फ्राड का पैसा मगां लेते है। हमलोग किसी दुकानदार के पास जाते है । उसका पेटीएम बाक्स साउण्ड व फोन पे साउण्ड बाक्स का शुल्क माफ कराने का झांसा देते है । फिर उससे कोई मोटी रकम अपने खाते मे स्थानान्तरित करवा लेते है । फिर उसके क्यूआर कोड पर पैसे वापस कर देते है । फिर उसके फोन पे में रिफंड की सेटिंग कर देते है । जिससे पैसे वापस ही मेरे खाते मे आ जाता है जो दुकानदार को पता नही चलता है। फिर वह पैसे को किसी सीएचसी या किसी दुकान पर जाकर अपनी इमरजन्सी व अपनी फर्जी आईडी दिखाकर/बताकर उनके खाते मे पैसा पेटीएम/फोनपे आदि से भेजकर नगद पैसा ले लेते है तथा आपस मे बांट लेते है । अभी कुछ दिन पहले मैं विशाल व अंकित दूबे बाराबंकी मे जाकर लगभग 48,525 रू/- का फ्राड किये थे उसके बाद पैसा आपस मे बाट लिये थें चन्द्रेश भी हम लोगो के साथ जनपद मऊ व बिहार राज्य मे भी जाकर फ्राड किये थे अंकित व चन्द्रेश के खाते में भी कई बार फ्राड का पैसा लिया गया था जिसकी शिकायत ऑनलाइन 1930 पर लोगों ने कर दिया था जिसके कारण इन लोगो के कई खाते बंद हो चुके है

'नए जीएसटी सुधारों से बढ़ेगी आमदनी-खपत', वित्त मंत्री बोलीं- जनता तक पहुंचेंगे दो लाख करोड़ रुपये

चेन्नई। देशभर में नए जीएसटी दरों को लेकर चर्चा तेज है। 22 सितंबर से लागू होने वाले इन दरों को लेकर लोगों ने अपनी मिली जुली प्रतिक्रियाएं भी दी है। ऐसे में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर इन नए दरों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर से लागू होने वाले नए जीएसटी सुधारों के कारण देश के लोगों के हाथ में लगभग दो लाख करोड़ रुपये बचेंगे, जिससे घरेलू खर्च और खपत बढ़ेगी।

तमिलनाडु फूडग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएसन के 80वें स्थापना दिवस समारोह में बोलते हुए सीतारमण ने कहा कि जीएसटी की दरों को चार स्लैब से घटाकर अब केवल दो स्लैब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इससे खासकर गरीब, मध्यम वर्गीय परिवार और छोटे-मध्यम उद्योग को फायदा मिले।

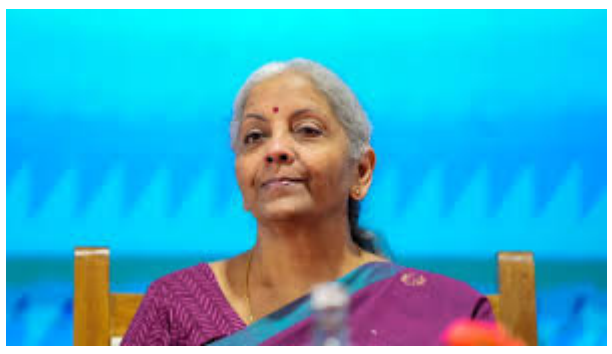

सामान की कीमतें होंगी कम- सीतरमण

सीतारमण ने कहा कि इस सुधार के बाद सामान की कीमतें कम होंगी, जिससे लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई साबुन ज्यादा मात्रा में खरीदता है, तो निर्माता उत्पादन बढ़ाएगा, जिससे रोजगार बढ़ेंगे और सरकार को अधिक टैक्स मिलेगा। यह एक सकारात्मक चक्र है जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा। इस दौरान वित्त मंत्री ने ये भी बताया कि जीएसटी लागू होने से पहले टैक्स देने वाले उद्यमियों की संख्या 65 लाख थी, जो अब बढ़कर 1.5 करोड़ हो गई है।

कांग्रेस की आलोचना पर भी दिया जवाब

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहकर आलोचना करने की बात पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि इसने टैक्स आधार बढ़ाया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पिछले आठ वर्षों में सरकार ने किसी उत्पाद पर ज्यादा टैक्स नहीं लगाया है और अब जो कटौती हो रही है वह सही और लोगों के हित में है। निर्मला सीतारमण का कहना है कि जीएसटी सुधारों से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और गरीब, मध्यम वर्ग व एमएसएमई को राहत मिलेगी।

भिवंडी में रिश्ता हुई तार तार,भाई ने अपनी चचेरी बहन के साथ किया 4 साल तक बलात्कार

बहन की शिकायत पर पुलिस ने किया हवसी भाई पर केस दर्ज,आरोपी हुआ फरार

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। भिवंडी में रिश्ते को तार तार किए जाने का मामला प्रकाश में आया है।एक नाई ने अपने चचेरी बहन को प्रेम जाल में फंसाकर 4 वर्षों तक बार बार अपनी हवस का शिकार बनाता रहा।आखिरकार बहन की शिकायत पर भोईवाड़ा पुलिस ने उसके चचेरे भाई पर बलात्कार का केस दर्ज किया है।जिसकी खबर लगते ही आरोपी फरार हो गया है।जिसकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है।इस घटना के उजागर होने के बाद लोगों में आश्चर्य व्याप्त है।

पुलिस के अनुसार आजमी नगर इलाके के टीपू सुल्तान चौक पर हुस्नेदिन मैनुद्दीन शाह (28) नामक व्यक्ति रहता है और केस कर्तनालय में नाई का काम करता है।जिसने अपनी चचेरी बहन को प्यार और शादी का झांसा दिया और 1 अगस्त 2021 से 19 सितंबर 2025 तक पीड़िता को अपने एक दोस्त के घर बुलाकर उसके साथ लगातार बलात्कार करता रहा। आखिरकार जब पीड़िता ने शादी के लिए अपने चचेरे भाई दबाव डाला तो उसने चचेरी बहन की बात मानने से इनकार कर दिया।जिसके बाद पीड़िता को जब अपने साथ हुई धोखाधड़ी का एहसास हुआ, तो पीड़िता भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन पहुँचकर पुलिस को अपने आपबीती की पूरी घटना सुनाई।जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर नाई के खिलाफ बीएनएस की धारा 69 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।जिसकी भनक मिलने के बाद आरोपी फरार हो गया।जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। घटना की जाँच उप-निरीक्षक नवनाथ रूपवते कर रहे हैं।

'सही फैसलों पर अपील क्यों?' कानून मंत्री मेघवाल ने सरकारी विभागों की प्रवृत्ति पर उठाए सवाल

नई दिल्ली।केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शनिवार को कहा कि सरकारी विभागों में न्यायालय के आदेशों को चुनौती देने की प्रवृत्ति को कम करना जरूरी है। वे यहां केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मेघवाल ने बताया कि कई बार कोर्ट या सीएटी द्वारा उचित और सही फैसले दिए जाने के बाद भी सरकारी विभाग और अधिकारी अपील दायर कर देते हैं।

उन्होंने संकेत दिया कि कभी-कभी अधिकारी अपने खिलाफ दिए गए निर्णयों को बचाने के लिए अपील दायर करते हैं। कानून मंत्री ने कहा कि उन्हें अक्सर ऐसे मामले मिलते हैं जहां केंद्र सरकार के विभाग मजबूत कोर्ट आदेशों के खिलाफ अपील करने की योजना बना रहे हैं।

मेघवाल ने आगे कहा कि सीएटी को न्याय में बाधा न बनने के लिए नवीनतम तकनीक जैसे ई-फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि भौगोलिक दूरी न्याय मिलने में बाधा न बने। मेघवाल ने ट्रिब्यूनल की भूमिका की भी सराहना की, जिससे सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों का केस भार कम हुआ है।

वैश्विक अयप्पा सम्मेलनः पिनरई बोले- सबरीमाला पर झूठा प्रचार बंद हो, मंदिर की आमदनी से एक रुपया नहीं लेती सरकार

पठानमथिट्टा (केरल)।केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने शनिवार को कहा कि यह जानबूझकर झूठ फैलाया जा रहा है कि सरकार सबरीमाला में किसी अल्पसंख्यक बैठक की योजना बना रही है। उन्होंने कहा, इस तरह का प्रचार केवल लोगों को गुमराह करने की एक राजनीतिक चाल है। पत्रकारों का काम है कि वह सच्चाई को ईमानदारी से सामने रखे , लेकिन कुछ लोग जानबूझकर झूठ फैलाते हैं। एक सुनियोजित झूठ कुछ लोगों को गुमराह कर सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा स्पष्ट रहती है। विजयन पठानमथिट्टा में वैश्विक अयप्पा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने आगे कहा, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि 2031 तक केरल को कैसे आगे ले जाना है, खासकर जब हम केरल के एकीकरण की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसी क्रम में अक्तूबर में 33 विभागीय सेमिनार होंगे, जिनकी मेजबानी संबंधित मंत्री करेंगे। इन सेमिनार से यह पता चलेगा कि केरल ने अब तक कितनी प्रगति की है और विकास की दिशा में आगे कैसे बढ़ना है।

विजयन ने कहा, कोरोना संकट के समय में देवस्वम बोर्ड की रोजमर्रा की गतिविधियां भी मुश्किल में आ गई थीं।

उस समय सरकार ने 140 करोड़ रुपये की मदद की। इसके अलावा, 129 करोड़ रुपये मंदिरों की मरम्मत के लिए दिए। 2011-12 से अब तक सबरीमाला मास्टर प्लान के तहत करीब 148 करोड़ रुपये विकास परियोजनाओं पर खर्ज किए गए हैं। हाल ही में सन्निधानम और पांबा में भी कार्यों को मंजूरी दी गई है। 2016-17 से 2025 तक देवस्वम संस्थानों के आधुनिकीकरण और विकास के लिए 680 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गई है, जिसमें त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के लिए 145 करोड़ रुपये, कोचीन देवस्वम बोर्ड के लिए 26 करोड़ रुपये, मालाबार देवस्वम बोर्ड के लिए 35 करोड़ रुपये, और पद्मनाभस्वामी मंदिर सहित अन्य संस्थानों के लिए अतिरिक्त राशि शामिल है। फिर भी यह झूठ फैलाया जाता है कि सरकार मंदिरों की आय ले रही है। सच्चाई यह है कि मंदिरों की आमदनी से सरकार ने एक भी रुपया नहीं लिया है। इसके विपरीत, सरकार लगातार मंदिरों की गतिविधियों को बनाए रखने, कर्मचारियों को वेतन देने और विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता देती रही है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, कुछ लोग सवाल करते हैं कि अब इस तरह तरह के आयोजन क्यों किए जा रहे हैं। इसका जवाब आसान है- समय बदल चुका है और भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए अब व्यापक और उच्च स्तर की सोच की जरूरत है। कुछ लोग तो अदालत तक चले गए थे ताकि ऐसे आयोजन रुक जाएं, लेकिन यह स्पष्ट है कि उनका उद्देश्य भक्ति नहीं था। यह मांग करना कि मंदिरों का प्रबंधन केवल श्रद्धालुओं को सौंपा जाए, इतिहास को नजरअंदाज करना है। यही श्रद्धालु पहले देवस्वम बोर्ड की मांग कर रहे थे,क्योंकि उस समय मंदिर बुरी हालत में थे। इन बोर्डों ने मंदिरों को फिर से खड़ा किया, कर्मचारियों का वेतन सुनिश्चितकिया और पूजा स्थलों को टूटने से बचाया।

उन्होंने कहा, सबरीमाला का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अद्वितीय है और इसे पूरी दुनिया के सामने पेश किया जाना चाहिए। यह जरूरी है कि यह तीर्थस्थल पूरी दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए अधिक सुलभ बने और बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए इसके विकास कार्य आगे बढ़ें। हमारा लक्ष्य है कि यात्रा कम थकाऊ हो और दुनियाभर के श्रद्धालु आसानी से यहां आकर पूजा करके सुरक्षित लौट सकें। इसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लेकर वर्चुअल कनेक्टिविटी तक हर संसाधन का इस्तेमाल होना चाहिए। हर भाषा में जानकारी और पंजीकरण सहायता केंद्र उपलब्ध होने चाहिए। अफसोस की बात है कि कुछ लोग इन प्रयासों को गलत तरीके से पेश करके समाज में भ्रम और विभाजन पैदा कर रहे हैं,जो सबरीमाला और उसके श्रद्धालुओं के हित के खिलाफ है।

'भरण-पोषण में असमर्थ पुरुष को नहीं है दूसरी शादी का हक', केरल हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

तिरुवनंतपुरम। केरल हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनावई के दौरान अहम और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई भी मुस्लिम पुरुष, जब तक वह अपनी पत्नियों का भरण-पोषण करने में सक्षम न हो, तब तक उसे दूसरी या तीसरी शादी करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि यहां तक की मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत भी नहीं। यह टिप्पणी जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने तब की जब एक 39 वर्षीय महिला ने अपने पति से ?10,000 मासिक गुजारा भत्ते की मांग करते हुए याचिका दायर की।

मामले में महिला का आरोप था कि उसका 46 वर्षीय पति जो नेत्रहीन है और भीख मांगकर जीवनयापन करता है, उसे छोड़कर पहली पत्नी के साथ रह रहा है और अब तीसरी शादी करने की धमकी दे रहा है। इससे पहले फैमिली कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि एक भिखारी से गुजारा भत्ता नहीं वसूला जा सकता। हाईकोर्ट ने भी इस पर सहमति जताई और कहा कि एक

भिखारी से गुजारा भत्ता दिलवाना अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

कोर्ट ने बार-बार शादी करने से जताई आपत्ति

हालांकि मामले में अदालत ने इस बात पर नाराजगी जताई कि आरोपी पति, जो खुद भीख मांगकर गुजारा करता है, वह बार-बार शादियां कर रहा है। अदालत ने कहा कि इस तरह की शादियां मुस्लिम समुदाय में अशिक्षा और धार्मिक कानूनों की सही जानकारी के अभाव में हो रही हैं। इस दौरान अदालत ने कुरान की आयतों का भी हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम बहुविवाह को सामान्य नहीं, बल्कि अपवाद मानता है और जब तक कोई पुरुष सभी पत्नियों के साथ न्याय नहीं कर सकता, उसे एक से अधिक शादियों की अनुमति नहीं है।

कोर्ट ने राज्य सरकार दो दिए निर्देश

अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई करे और इस व्यक्ति को धार्मिक नेताओं की मदद से काउंसलिंग दी जाए। साथ ही, पीड़ित पत्नी को सरकार की ओर से भोजन और कपड़े की सुविधा दी जाए ताकि उसका जीवन सुरक्षित रह सके। यह फैसला सामाजिक चेतना और मुस्लिम पर्सनल लॉ की व्याख्या दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

यूपी के चिकित्सालय में तैनात कार्मिक होंगे प्रशिक्षित, जानें कैसे मरीजों को होगा फायदा

उत्तर प्रदेश के निवासियों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सकीय सुविधाएं सुलभ कराने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में लागू की जाने वाली इस योजना के तहत अब राज्य के 75 जनपदों में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) के चिकित्सा अधीक्षक/लैब टेक्नीशियनों/कम्प्यूटर आपरेटरों को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का शुभारंभ किया गया है। यह प्रशिक्षण जिलों के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) के पर्यवेक्षण में दिया जा रहा है।

15 सितंबर से शुरू किए गए इस प्रशिक्षण को मेसर्स पीओसीटी सर्विसेज के एनजीओ पीक्यूएसडीएफ के द्वारा सीएसआर फंड से संचालित किया जा रहा है। चिकित्सालयों में तैनात मानव संसाधन के प्रशिक्षित हो जाने के बाद प्रत्येक मरीज का आभा आधारित पंजीकरण होगा एवं उनका डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड तैयार होने के साथ-साथ सभी को कम्प्यूटराइज्ड पैथालॉजी रिपोर्ट उनके मोबाइल पर वाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी।

यूपी के 75 जिलो में चलेगा ट्रेनिंग अभियान

क्या है योजना

यूपी सरकार ने अपने अस्पतालों में मरीजों के लिए सुविधा शुरू की थी, जिसमे किसी को टेस्ट रिपोर्ट पाने के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें ऑनलाइन ही हासिल किया जा सकेगा।

क्या कहना है ट्रेनिंग देने वाली कंपनी का

यूपी के 75 जिलो के सभी अस्पतालों में ट्रेनिंग देने वाली पीओसिटी के चैयरमैन का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में लैब टेस्ट की रिपोर्ट एसएमएस के जरिए मोबाइल पर मुहैया कराने की सुविधा से बहुत से मरीजों और उनके परिजनों को मदद मिली है और उन्हें अस्पताल में आकर लाइन में नहीं लगना पड़ रहा है। इसी कड़ी में अब पीओसिटी ने उत्तर प्रदेश के तमाम चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को बड़ी राहत देने के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन शुरू किया गया है। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक महीने तक जारी रहेगा।

यूपी के अलग-अलग मंडलों में अलग-अलग जिलों में अनुभवी ट्रेनर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिये सही ट्रेनिंग देंगे जिससे मरीजों को सही समय पर सही जांच रिपोर्ट उपलब्ध हो सके।

चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, बंगाल के 12 राजनीतिक दलों समेत 474 निष्क्रिय पार्टियों को सूची से हटाया

कोलकाता।भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के अपने निरंतर प्रयास के तहत, भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने शुक्रवार को देश भर के 474 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया, जिनमें पश्चिम बंगाल के 12 दल भी शामिल हैं। एक अधिकारी ने बताया कि ये दल लगातार छह वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ने के कारण सूची से बाहर हो गए हैं।

उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में सूची से हटाए गए दलों में अंबेडकरवादी पार्टी, ग्लोबल पीपल पीस पार्टी और गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट जैसे कम-ज्ञात या लंबे समय से निष्क्रिय संगठन शामिल हैं, जो कभी क्षेत्रीय पहचान आंदोलनों से जुड़े थे। सूची से हटाए गए अन्य

दलों में कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी, माई ही भारत, नेशनल कॉन्फेडेरसी ऑफ इंडिया और राष्ट्रवादी तृणमूल कांग्रेस पार्टी शामिल हैं।

इन पार्टियों को भी सूची से किया गया बाहर

इसके अलावा, पर्वतीय प्रजातांत्रिक पार्टी, पश्चिम बंग राज्य मुस्लिम लीग, और राइट पार्टी ऑफ इंडिया और रिलिजन ऑफ मैन रिवॉल्विंग पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया जैसी अज्ञात संस्थाओं को भी सूची से बाहर कर दिया गया। रिवॉल्विंग पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया चुनावी गतिविधियों से ज्यादा अपने विचित्र नाम के लिए जानी जाती है।

यह कार्रवाई चुनाव आयोग के राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा

चुनाव आयोग की यह कार्रवाई एक बड़े राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ऐसे निष्क्रिय या नियमों का पालन न करने वाले दलों की पहचान करना है जो चुनावी प्रक्रिया में भाग न लेकर भी वैधानिक विशेषाधिकारों का लाभ उठा रहे थे।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत चुनाव आयोग में पंजीकृत दलों को आरक्षित चुनाव चिह्न और कर छूट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि, दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लगातार छह वर्षों तक चुनाव न लड़ने वाले दलों को सूची से हटाया जा सकता है।

केजरीवाल का बीजेपी पर तीखा हमला: 4 इंजन वाली सरकार राजधानी की सुरक्षा में फेल

आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को शहर के स्कूलों को बार-बार बम की धमकियाँ मिलने पर सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की आलोचना की।ं पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक साल में स्कूलों को बार-बार बम की धमकियाँ मिलने के बावजूद, अभी तक किसी को पकड़ा नहीं गया है। केजरीवाल ने लिखा कि दिल्ली के स्कूलों को बार-बार बम की धमकियाँ मिल रही हैं। हर जगह दहशत फैल गई है, स्कूल बंद हैं और बच्चों और अभिभावकों में डर फैल रहा है... लेकिन एक साल में न तो कोई पकड़ा गया है और न ही कोई कार्रवाई की गई है।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के सरकारी प्रबंधन की तीखी आलोचना की और इस बात पर ज़ोर दिया कि अभिभावक हर दिन डर के साये में जी रहे हैं। केजरीवाल ने पूछा, 'चार इंजन वाली भाजपा सरकार राजधानी की सुरक्षा भी नहीं संभाल पा रही है। माता-पिता हर दिन डर के साये में जी रहे हैं। यह सब कब खत्म होगा?' इससे पहले, दिल्ली के विभिन्न इलाकों के कई स्कूलों को आज सुबह फ़ोन कॉल के ज़रिए बम की धमकियाँ मिलीं। जिन स्कूलों को ये धमकियाँ मिलीं उनमें डीपीएस द्वारका, कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल और सर्वोदय विद्यालय शामिल थे। एहतियात के तौर पर, छात्रों और कर्मचारियों को परिसर से बाहर निकाल लिया गया।

धमकियों के बाद, पुलिस दल और बम निरोधक दस्ते तुरंत स्कूलों में भेजे गए। लक्ष्यित स्कूलों में से एक, डीपीएस द्वारका ने आज अपना स्कूल बंद कर दिया है और 'अपरिहार्य परिस्थितियों' का हवाला देते हुए उस दिन होने वाली मध्यावधि परीक्षाएँ स्थगित कर दी हैं।

ऐतिहासिक उपलब्धिः मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में सुरंग निर्माण में बड़ी सफलताङ ङसमाज के एक बड़े वर्ग के लिए सुगम्यता सुनिश्चित करने हेतु मध्यम-वर्गीय किराया संरचना के साथ आरामदायक यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में, भारत ने मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना में एक ऐतिहासिक इंजीनियरिंग उपलब्धि हासिल की है।

मनोरंजन

नहीं रहे प्रसिद्ध गायक जुबीन गार्ग! गायक का पार्थिव शरीर भारत लाया जाएगा; सिंगापुर में पोस्टमॉर्टम किया गया

मुंबई। प्रसिद्ध गायक जुबीन गार्ग का सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान एक दुर्घटना में निधन हो गया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के प्रतिनिधि ने सिंगापुर में उनकी अचानक मौत की खबर की पुष्टि की। उनके चाहने वाले और प्रशंसक उनके निधन पर शोक जता रहे हैं, वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा गायक का पार्थिव शरीर वापस लाने की प्रक्रिया की देखरेख कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि जुबीन गार्ग का पोस्टमॉर्टम सिंगापुर में पूरा हो गया है और उनका पार्थिव शरीर जल्द ही सौंप दिया जाएगा। पोस्ट में लिखा था, 'हमारे प्यारे जुबीन गार्ग का पोस्टमॉर्टम सिंगापुर में पूरा हो गया है। उनका पार्थिव शरीर अब साथ आई टीम - शेखर ज्योति गोस्वामी, संदीपन गार्ग और सिद्धार्थ शर्मा (मैनेजर) - को भारतीय दूतावास के अधिकारियों की उपस्थिति में सौंपा जा रहा है।'

जुबीन की मौत की खबर की पुष्टि नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के प्रतिनिधि ने सिंगापुर में की। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के प्रतिनिधि अनुज कुमार बरुआ ने कहा, 'हमें जुबीन गार्ग के निधन की खबर बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। स्कूबा डाइविंग करते समय उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई और उन्हें तुरंत सीपीआर दिया गया और सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्हें बचाने की कोशिश के बावजूद, उन्हें शाम 2.30 बजे आईसीयू में मृत घोषित कर दिया गया।'

जुबीन ने 1992 में एक पेशेवर गायक के रूप में अपना करियर शुरू किया और अपना पहला एल्बम 'अनामिका' जारी किया। बाद में उन्होंने 1993 में अपने पहले गाने 'तुमि जूनु पारिबा हुन' और 'तुमि जूनकी हुबाख' रिकॉर्ड किए। 1995 में मुंबई जाने से पहले उन्होंने अपना पहला बीहू एल्बम, उजन प्रीति जारी किया। उन्हें 2006 में फिल्म 'गैंगस्टर' के गाने 'या अली' से प्रसिद्धि मिली।

योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग : अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी

भोपालः मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच व हिन्दू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है। उन्होंने सनातन धर्मियों से इस फिल्म को देखने की अपील भी की है। तिवारी ने

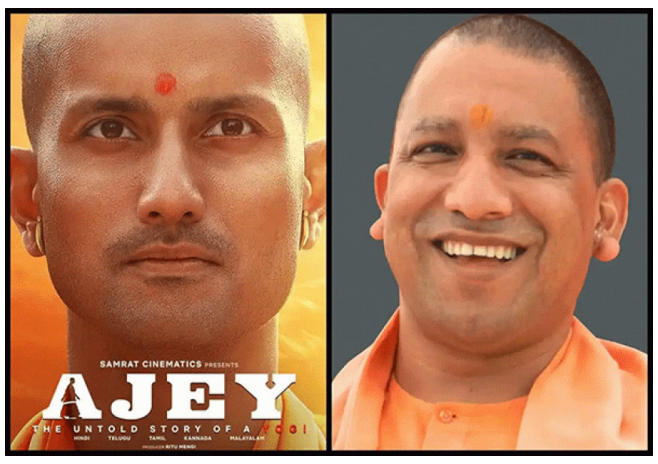

कहा कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तरप्रदेश में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलाकर, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मजनू जैसे ऐतिहासिक कार्य किए, जिनसे प्रदेश की विश्व स्तर पर सराहना हुई।

साथ ही गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के जीवन का परिचय फिल्म में पूरा दर्शाया गया है। चन्द्रशेखर तिवारी ने कहा कि उत्तरप्रदेश में मौलाना फिल्म के खिलाफ फतवा जारी कर रहे हैं, जो एक पब्लिसिटी स्टंट है। तिवारी ने उठाया कि क्या वे सलमान, शाहरुख और आमिर खान की फिल्में नहीं देखते।

ऑस्कर 2026 के लिए 'होमबाउंड' नामित

मुंबई : नीरज घायवान की फिल्म 'होमबाउंड' को ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है। यह फिल्म के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और टीम इस खबर से बहुत खुश है। प्रोड्यूसर करण जौहर , डायरेक्टर नीरज घायवान और कास्ट ने इस शानदार मौके के लिए अपना आभार व्यक्त किया है।

लेकिन ऑस्कर के लिए भारत की एंट्री का यह सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है?

भारत में, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया तय करता है कि एकेडमी अवार्ड के लिए भारत की कौन सी फिल्म भेजी जाएगी। इइघ में कथित तौर पर 13 जूरी सदस्य हैं, जो इस सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। जूरी चर्चा करती है और वोटिंग करके फिल्म चुनती है और फिर आधिकारिक घोषणा करती है। फिल्में 1 अक्टूबर से अगले साल 30 सितंबर के बीच रिलीज होनी चाहिए और कम से कम 60 प्रतिशत डायलॉग भारतीय भाषाओं में होने चाहिए।

जानें होमबाउंड' के बारे और भी बहुत कुछ

यह फिल्म 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। यह फिल्म 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और मेलबर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई गई थी। भारत में रिलीज होने से पहले ही 'होमबाउंड' को क्रिटिक्स से शानदार रिस्पॉन्स मिला था।

ऑस्कर 2026 के लिए 'होमबाउंड' को भारत की एंट्री बनाए जाने पर खुशी जताते हुए करण जौहर ने एक बयान में कहा, 'हमें बहुत गर्व और खुशी है कि 'होमबाउंड' को एकेडमी अवार्ड के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है... नीरज घायवान की यह फिल्म दुनिया भर में लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाएगी।'

नीरज घायवान ने कहा, 'मुझे बहुत गर्व है कि 'होमबाउंड' को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है। यह हमारी धरती और हमारे लोगों के प्रति प्यार से बनी है और इसमें हम सभी के घर की भावना है। अपनी कहानियां दुनिया के सामने रखना और सिनेमा के सबसे बड़े ग्लोबल मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना बहुत गर्व की बात है और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं।' 'होमबाउंड' 26 सितंबर, 2025 को भारत में रिलीज होगी। इसमें ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं।

दुबई में पाकिस्तान से 'महाजंग', सूर्यकुमार की हुंकार- टीम इंडिया पूरी तरह तैयार

दुबई। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप के सुपर फ़ोर में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच से पहले भारत की तैयारियों पर भरोसा जताया है। भारत रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एशिया कप 2025 के सुपर 4 चरण में दूसरी बार पाकिस्तान से भिड़ेगा। भारत के एशिया कप अभियान की शानदार शुरुआत हुई है, टीम ने यूएई, पाकिस्तान और ओमान के खिलाफ ग्रुप चरण के तीनों मैच जीते हैं। सूर्यकुमार ने एकाग्र दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया और अपनी टीम से पिछली सफलताओं पर निर्भर रहने के बजाय एक-एक करके हर मैच पर ध्यान देने का आग्रह किया।

मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'मुझे लगता है कि टूर्नामेंट से पहले हमारी तैयारियाँ बेहतरीन रही हैं और हमने 3 अच्छे मैच भी खेले हैं, इसलिए हम असल में इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने टॉस के समय भी कहा था, हम अपनी सभी अच्छी आदतों को अपनाना चाहते हैं, जो हम पिछले 2-3 मैचों से कर रहे हैं और हम एक समय में एक ही मैच पर ध्यान देंगे। लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा, इससे हमें कोई बढ़त नहीं मिलती, क्योंकि हम उनसे एक बार खेल चुके हैं और हमारा मैच अच्छा रहा है, इसलिए निश्चित रूप से यह एक अच्छा मैच होगा। हमें शुरुआत से ही अच्छी शुरुआत करनी होगी और जो भी अच्छा खेलेगा, वही मैच जीतेगा।'

हाथ न मिलाने, विचार-विमर्श और मैच से हटने की धमकियों जैसे नए विवादों के बाद, भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने-सामने होंगे। यह विवाद तब शुरू हुआ जब भारत ने रविवार को दुबई में चल रहे एशिया कप के मुकाबले में 7 विकेट से शानदार जीत हासिल करने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने का फैसला किया। पाकिस्तान ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और मैच के बाद की प्रस्तुति से हटकर अपनी निराशा व्यक्त की।

भारत का यह रुख जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों से जुड़ा था, जिसमें 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों को मार डाला था। पीसीबी द्वारा पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने और उन पर आईसीसी आचार संहिता और क्रिकेट भावना से संबंधित एमसीसी कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाने के बाद हाथ मिलाने का विवाद और बढ़ गया। हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने पाकिस्तान के अनुरोध को मानने से साफ इनकार कर दिया। जवाब में, पीसीबी ने यूएई के खिलाफ करो या मरो वाले मैच से हटने की धमकी दी।

भारत-पाक महामुकाबले में फिर रेफरी होंगे एंडी पाइक्रॉफ्ट

दुबई।एंडी पाइक्रॉफ्ट एक बार फिर से एशिया कप में भारत और पाकिस्तान बीच होने वाले सुपर 4 मुकाबले में मैच रेफरी होंगे। एंडी पाइक्रॉफ्ट 14 सितंबर को एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले में हाथ मिलाने को लेकर हुए विवाद के केंद्र में थे। भारत के खिलाफ 7 विकेट से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने पाइक्रॉफ्ट को तुरंत हटाने की मांग की थी। पाकिस्तान बोर्ड के अनुसार, पाइक्रॉफ्ट ने कप्तान सलमान आगा और सूर्यकुमार यादव से ग्रुप स्टेज मुकाबले के टॉस के दौरान हाथ न मिलाने को कहा था।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने पीसीबी की अपील नहीं मानी और जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर वहीं रुके रहे। हालाँकि, यह विवाद पाकिस्तान के यूएई के खिलाफ होने वाले करो या मरो वाले मैच तक फैल गया। मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करने के बाद, पाकिस्तान दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में देर से पहुँचा और मैच एक घंटे की देरी से शुरू हुआ। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को होटल में रुकने के लिए कहा गया, जबकि पीसीबी अधिकारी आईसीसी के साथ गुप्त बातचीत में लगे रहे।

यूएई के खिलाफ पाकिस्तान के टॉस से कुछ देर पहले, पाकिस्तानी टीम प्रबंधन ने पाइक्रॉफ्ट से मुलाकात की, जिससे एक और विवाद खड़ा हो गया। पीसीबी ने इस मुलाकात का एक म्यूटेड वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। इसी पृष्ठभूमि में दोनों टीमें एक बार फिर उसी मैदान पर आमने-सामने होंगी। मैदान के बाहर के ड्रामे के बीच, सूर्यकुमार ने आगे की चुनौती पर ध्यान केंद्रित किया और शनिवार को पत्रकारों से कहा, 'मुझे लगता है कि टूर्नामेंट से पहले हमारी तैयारी वाकई अच्छी रही है। और हमने तीन अच्छे मैच भी खेले हैं। इसलिए हम असल में इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि हम क्या सबसे अच्छा कर सकते हैं। हम उन सभी अच्छी आदतों को अपनाना चाहते हैं, जो हम पिछले दो-तीन मैचों से कर रहे हैं। और हम एक बार में एक मैच पर ध्यान देंगे।'

मौजूदा चैंपियन हरियाणा स्टीलर्स ने पुनेरी पलटन को हराया!

जयपुरः प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन के 41वें मुकाबले में हरियाणा स्टीलर्स ने सांस रोक देने वाले रोमांच के बाद पुनेरी पलटन को 34-30 के अंतर से हरा दिया। परिणाम चाहें जो भी रहा लेकिन इसमें कबड्डी की जीत हुई। हरियाणा की यह सात मैचो में पांचवीं जीत है जबिक पल्टन को नौ मैचों में तीसरी हार मिली।

सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में हरियाणा की जीत में विनय (13) और शिवम (8) का अहम योगदान रहा। यह शिवम ही हैं, जिन्होंने दो अंक की रेड के साथ हरियाणा की जीत पक्की की। डिफेंस में कप्तान जयदीप ने चार और राहुल सेतपाल ने तीन शिकार किए। पलटन के लिए पंकज मोहिते (14) ने अपना श्रेष्ठ खेल दिखाया और एक समय 10 अंक से पिछड़ रही टीम की उसे इस स्थिति से निकाल लिया। अगली रेड पर हालांकि सेतपाल ने आदित्य को लपक लिया।

वापसी कराई लेकिन वह उसे जीत नहीं दिला सके।

दो अच्छी टीमों के बीच मुकाबला जोरदार तरीके से शुरू हुआ। 2-0 से लीड लेने के बाद हरियाणा ने ग्रिप खोया लेकिन फिर भी पांच मिनट के बाद उसे 5-2 की लीड मिली हुई थी। इसके बाद गुरदीप का शिकार कर शिवम पलटन न को सुपर टैकल की स्थिति में ले आए। शिवम ने अगली रेड पर अबिनेश को आउट कर पलटन को आलआउट की ओर धकेल दिया। जयदीप ने असलम को डैश कर पलटन को आलआउट कर हरियाणा को 11-2 की लीड दिला दी।

आलइन के बाद हरियाणा ने दो के मुकाबले चार अंक लेकर 14-4 के स्कोर पर ब्रेक पर गई। ब्रेक के बाद पलटन ने चार अंक लेकर वापसी की राह पकड़ी। इस दौरान हालांकि उसने एक अंक गंवाया भी। फासला अब 7 का रह गया था। आदित्य लगातार अंक ले रहे थे। हरदीप को आउट कर वह हरियाणा को सुपर टैकल की स्थिति में ले आए लेकिन विनय ने इस बीच गुरदीप ने डू ओर डाई रेड पर विनय को लपक स्कोर 10-17 कर दिया लेकिन साहिल ने इसी तरह की रेड पर पंकज को डैश कर हिसाब बराबर किया। फिर शिवम ने डू ओर डाई रेड पर गौरव को आउट कर हाफटाइम तक स्कोर 19-10 कर दिया। हाफटाइम के बाद पलटन के डिफेंस ने शिवम और विनय का शिकार कर लिया। हरियाणा के डिफेंस ने हालांकि सचिन को डैश कर शिवम को रिवाइव कराया और आते ही उन्होंने स्कोर 22-12 कर दिया। पंकज ने हालांकि अगली रेड पर सेतपाल और शिवम का शिकार कर लिया। अगली रेड पर भी पंकज सफल रहे लेकिन विनय ने सुपर रेड के साथ पलटन की वापसी पर ब्रेक लगा दिया। 30 मिनट के बाद हरियाणा को 25-16 की लीड मिली हुई थी। ब्रेक के बिनय ने अबिनेश का शिकार कर फासला फिर 10 का कर दिया। पंकज ने हालांकि दो रेड में तीन अंक लेकर फासला 7 कर दिया। अगली रेड पर पंकज फिर दो अंक लेकर लौटे और हरियाणा को दो खिलाड़ियों तक सीमित कर दिया।

सेबी ने 'नॉमिनी' से कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रतिभूति हस्तांतरण के नियम को सरल बनाया

नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने को 'नॉमिनी' यानी नामित व्यक्ति से कानूनी उत्तराधिकारी को प्रतिभूतियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल कर दिया। फिलहाल जब कोई नामित व्यक्ति किसी कानूनी उत्तराधिकारी को प्रतिभूतियां हस्तांतरित करता है तो इस लेनदेन को कभी-कभी 'हस्तांतरण' माना जा सकता है और उसका आकलन पूंजीगत लाभ कर लगाने के रूप में किया जा सकता है।

हालांकि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 47(तीन) के तहत इस तरह के हस्तांतरण पर कर नहीं लगना चाहिए। नामित व्यक्ति बाद में धनवापसी का दावा कर सकता है लेकिन इससे उसे अनावश्यक असुविधा होती है।

इस समस्या के समाधान के लिए एक कार्य समूह ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से परामर्श किया और एक नए रिपोर्टिंग कोड 'टीएलएच' (कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरण) के उपयोग की सिफारिश की। यह कोड यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि ऐसे हस्तांतरण की सही ढंग से सूचना दी जाए और उन पर पूंजीगत लाभ के रूप में कर नहीं लगाया जाए। सेबी ने अपने परिपत्र में कहा, "यह निर्णय लिया गया है कि नामित व्यक्ति से कानूनी उत्तराधिकारी को प्रतिभूतियों के हस्तांतरण की रिपोर्ट करते समय रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा सीबीडीटी को एक मानक कोड 'टीएलएच' का उपयोग किया जाएगा ताकि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का उचित उपयोग हो सके।"

एक जनवरी, 2026 से आरटीए (पंजीयक और हस्तांतरण एजेंट), सूचीबद्ध कंपनियों, डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों सहित सभी रिपोर्टिंग संस्थाएं, सीबीडीटी को इन लेनदेन की रिपोर्ट करते समय 'टीएलएच' कोड का उपयोग करेंगी। इससे पहले सेबी ने नामित व्यक्तियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया था।

नामित व्यक्ति मूल प्रतिभूति धारक की प्रतिभूतियों के ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है और उत्तराधिकार योजना के अनुरूप प्रतिभूतियों को कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित करता है।

लगातार तीन हार के बाद तेलुगू टाइटंस की वापसी, तमिल थलाइवाज को 14 अंक से हराया!

जयपुरः लगातार तीन हार के बाद तेलुगू टाइटंस ने शुक्रवार को वापसी करते हुए प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन के 42वें मुकाबले में तमिल थलाइवाज को 43-29 के अंतर से हरा दिया। नौ मैचों में टाइटंस की यह चौथी जीत है जबकि थलाइवाज को छह मैचों में तीसरी हार मिली। आज यहां सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टाइटंस की जीत में उसके डिफेंस (13) का अहम योगदान रहा। साथ ही रेड में विजय मलिक (10) और भरत (8) ने बेहतरीन खेल दिखाया। अंकित ने चार टैकल किए।

थलाइवाज के लिए अर्जुन देसवाल (7) अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर सके। कंडोला (6) अच्छा खेले और डिफेंस मे रौनक (4) ने भी चमक दिखाई। इस जीत ने टाइटंस को शीर्ष-4 में पहुंचा दिया है।

शुरुआती 4 मिनट में टाइटंस ने बेहतर खेल दिखाते हुए 4-1 की लीड ले ली थी। विजय औ? भरत ने बराबर योगदान दिया था। देसवाल ने थलाइवाज के लिए एक अंक लिया और फिर डू ओर डाई रेड पर उन्होंने भरत का शिकार कर स्कोर 2-4 कर दिया। लेकिन अगली रेड पर अंकित ने उनका शिकार कर लिया। फिर भरत ने रनिंग हैंड टच पर आकाश को बाहर कर दिया। फिर कंडोला को आउट कर डिफेंस थलाइवाज को सुपर टैकल की स्थिति में ले आए। थलाइवाज इसका लाभ नहीं ले सके और दो खिलाड़ियों तक सीमित हो गए। टाइटंस ने इसके बाद पहला आलआउट लेते हुए 13-4 की लीड ले ली। ब्रेक के बाद थलाइवाज ने एक के मुकाबले चार अंक लेकर टाइटंस को सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया। फिर देसवाल ने एक अंक के साथ टाइटंस को दो खिलाड़ियों तक सीमित कर दिया।

सुपर टैकल की स्थिति में शंकर ने देसवाल को लपका और फिर विजय ने दो अंक की रेड के साथ आलआउट बचाते हुए स्कोर 19-9 कर दिया। अब थलाइवाज के लिए सुपर टैकल आन था। हाफटाइम तक टाइटंस 22-10 से आगे थे और थलाइवाज का एक खिलाड़ी मैट पर था। ब्रेक के बाद बेनीवाल ने मल्टीप्वाइंटर के साथ थोडे समय के लिए थलाइवाज को मुश्किल से बचाया लेकिन फिर टाइटंस ने आलआउट लेकर 26-13 की लीड ले ली। आलइन के बाद टाइटंस ने एक बार फिर थलाइवाज को एक खिलाड़ी तक सीमित किया लेकिन रौनक ने उसे आलआउट से बचाया औ? फिर डिफेंस ने भरत को लपक सुपर टैकल के दो अंक ले लिए।

पश्चिम रेलवे

सामग्री प्रबंधन विभाग

विभिन्न सामग्री आपूर्ति

ई-खरीद निविदा सूचना संख्याः एस/61/2025 दिनांक 17.09.2025

अ.क्र.	आइटम का संक्षिप्त विवरण	मात्रा	टी.ओ.डी
524	रोटेक्स निर्मित चुंबकीय वाल्व।	660 Nos	13-Oct-25
525	WAP-4 लोकोमोटिव के लिए एयर ब्रेक सिलेंडर असेंबली 8' X 8'।	790 Nos	14-Oct-25
526	जम्पर प्लग के लिए एडाप्टर असेंबली।	3416 Nos	14-Oct-25
527	BL स्विच पूर्ण।	272 Nos	15-Oct-25
528	WAG-9 के लिए एक्सल गाइड और टॉर्क आर्म के लिए स्फेरी ब्लॉक।	996 Nos	16-Oct-25
529	इलेक्ट्रो न्यूमेटिक प्रेशराइज्ड फ्लशिंग सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग	1200 Set	16-Oct-25
530	उन्नत उच्च तन्यता वाला टाइट लॉक	120 Set	16-Oct-25
531	एलएचबी प्रकार के डिब्बो के लिए स्थिर खिड़की हेतु ग्लास यूनिट	8523 Nos	16-Oct-25
532	स्वचालित ट्विस्ट लॉक।	1080 Nos	03-Nov-25
533	बॉक्सन वैगन के लिए कपलर रॉड	13926 Nos	05-Nov-25
534	बीसीएनए वैगन से आरडीएसओ डीआरजी संख्या WD-90030-S-66 के लिए फ्लैप डोर	2186 Nos	10-Nov-25
535	द्वितीय और तृतीय एसी कोचों के लिए तकिया	85372 Nos	10-Nov-25
536	3 फेज़ मापन और निगरानी रिले रेटेड वोल्टेज	1350 Nos	12-Nov-25
537	ट्रैक्शन सेंटर इलास्टिक जॉइंट	4284 Nos	12-Nov-25
538	लेड एसिड बैटरी 300 AH	20 Nos	17-Nov-25
539	MK-50 ड्राफ्ट गियर के लिए पतला स्थिर प्लेट	2592 Nos	17-Nov-25
540	MK-50 ड्राफ्ट गियर के लिए चल प्लेट	2592 Nos	18-Nov-25
541	चेयर कार के लिए द्वितीयक स्प्रिंग बाहरी	131 Nos	24-Nov-25

विस्तृत सूचना ईएमडी, खरीद प्रतिबंध और विस्तृत निविदा शर्तों के संबंध में, कृपया वेबसाइट www.ireps.gov.in और wr.indianrailways.gov.in देखें।

0612

Like us on: facebook.com/WesternRly • Follow us on: X.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे - अहमदाबाद मण्डल

ई-निविदा सूचना संख्याः 06 2025-26 दिनांकः 18/09/2025

PLASSER बनावट के प्लेन ट्रैक टेम्पर्स मशीनों के टेंम्पींग युनिट्स का रिकंडिशनींग/ओवरह्योलिंग

निविदा सं. CWMCPOHADI2025-26-06

कार्य का नामः CPOH अहमदावाद अंतर्गत POH एवं CR, WCR, NWR एवं WR जोन में कार्य करने दौरान वर्ष 2025-26 के लिए CSM/WST/DUOMATIC और CSM-3x/HOT-3x जैसे Plasser बनावट के प्लेन ट्रैक टेम्पर्स मशीनों के टेम्पींग यूनिट्स का रिकंडिशनींग/ओवह्योलिंग।

NIT की अनुमानित लागतः ₹17,61,80,169/-

ईएमडी शुल्क रु. मेंः ₹10,30,900/-

निविदा बंद होने एवं खुलने की तारीख एवं समयः दिनांकः 16-10-2025 को 11:00 बजे एवं दिनांक 16/10/2025 को 11:15 बजे

ADI-166

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: X x.com/WesternRly

4 लाख से अधिक शहरी क्षेत्र की महिलाओं ने रोजगार योजना में किया आवेदन

पटना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने ग्रामीण और शहरी, हर वर्ग की महिलाओं में नई उम्मीद जगाई है। इस योजना ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हुए स्वालंबी बनाने का रास्ता प्रशस्त कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्र के अलावा शहरी इलाके की महिलाएं भी बड़ी संख्या में इसका लाभ लेने के लिए रूचि दिखा रही हैं। अब तक शहरी इलाकों में कार्यरत 4 लाख 66 हजार जीविका दीदियों ने योजना के तहत आवेदन किया है। इसके साथ ही जीविका के अंतर्गत संचालित स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) से जुड़ने के लिए 4 लाख 4 हजार से ज्यादा शहरी महिलाओं ने भी आवेदन किया है।

इस योजना के जल्द शुरू होने की संभावना है। इसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 50 लाख महिलाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त भेजेंगे। कुल 5 हजार करोड़ रुपये की राशि का वितरण महिलाओं के बीच किया जाएगा। ताकि वे इसकी मदद से अपना कोई कारोबार शुरू कर सकें। हर पात्र परिवार की एक महिला को यह राशि दी जानी है। पहली किस्त की राशि लेकर वे खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई-बुनाई या छोटे-मोटे उद्यम शुरू कर सकती हैं।

इसके बाद इन्हें 2 लाख रुपये सहायता करीब छह महीने बाद दी जाएगी, जिससे वे अपना व्यवसाय बढ़ा सकें।

1 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाओं ने किया आवेदन

इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मजबूती के लिए बराबर मौका देना है। ग्रामीण क्षेत्र की एसएचजी से जुड़ी 1 करोड़ 5 लाख जीविका दीदियों ने लाभ लेने के लिए आवेदन किया है। साथ ही 1 लाख 40 हजार से ज्यादा महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने के लिए आवेदन किया है।

ये उठा सकते हैं योजना का लाभ

योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा, जिनमें पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल हैं। वैसी अविवाहित वयस्क महिलाएं जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं, वह भी पात्र होंगी। आवेदिका की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदिका या उनके पति आयकर दाता नहीं होने चाहिए। साथ वे या उनके पति सरकारी सेवा (नियमित या संविदा) में नहीं होना चाहिए। जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी।

यह है आवेदन की प्रक्रिया

ग्रामीण क्षेत्र :- एसएचजी से जुड़ी महिलाएं अपने ग्राम संगठन में आवेदन जमा करेंगी। ग्राम संगठन स्तर पर एक विशेष बैठक आयोजित होगी, जिसमें समूह के सभी सदस्यों का एक समेकित प्रपत्र में आवेदन लिया जाएगा। जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं उन्हें पहले अपने ग्राम संगठन में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देकर समूह में शामिल होना होगा।

शहरी क्षेत्र :- शहरी क्षेत्र की महिलाएं जीविका की आधिकारिक वेबसाइट www.brlps.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। पूर्व से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी शहरी महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।

वन मंत्री डॉ सुनील कुमार ने किया थावे इको पार्क का शिलान्यास, 18 करोड़ की लागत से बनेगा इको पार्क

पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और स्थानीय पर्यटन को नई दिशा देने के लिए गोपालगंज जिले के थावे में इको पर्यटन पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना का शिलान्यास शनिवार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉ सुनील कुमार ने किया। करीब 18 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह इकोपर्यटन पार्क न केवल जिले के लोगों को मनोरंजन और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कराएगा। बल्कि, राज्य के पर्यटन क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाएगा।

मंत्री ने बताया कि इस परियोजना में आधुनिकता और प्राकृतिक आकर्षण का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। इसमें ओपन एम्पीथिएटर बनाया जाएगा, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम और जन-जागरूकता से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जा सकेंगी। साथ ही आगंतुकों के लिए पार्क कैफेटेरिया का भी निर्माण किया जाएगा। बच्चों के मनोरंजन के लिए प्ले जोन विशेष आकर्षण का केंद्र होगा, जहां सुरक्षित और रोचक खेल उपकरण लगाए जाएंगे।

पार्क की सुरक्षा और सौंदर्य बढ़ाने के लिए बैम्बू फेंसिंग बैरियर और बैम्बू स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। जिपलाइन और लंगूर नेट जैसी एडवेंचरस गतिविधियां युवाओं और पर्यटकों के बीच खास आकर्षण होंगी। वहीं, साइकिल शेड और वॉकवे स्वास्थ्यप्रेमियों को प्रकृति के बीच सैर का अवसर देंगे। उन्होंने कहा कि पार्क में पर्यावरण-अनुकूल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। सोलर लाइट से पार्क की रोशनी की व्यवस्था की जाएगी, जिससे ऊर्जा की बचत होगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। आगंतुकों के विश्राम के लिए आरसीसी बेंच की सुविधा होगी। बर्ड वॉचिंग की विशेष व्यवस्था की जाएगी, जहां पक्षी प्रेमी प्राकृतिक वातावरण में दुर्लभ प्रजातियों का अवलोकन कर सकेंगे। इसके अलावे भव्य मुख्य द्वार बनाया जाएगा और शौचालय जैसी मूलभूत संरचनाएं भी विकसित की जाएंगी। डॉ सुनील कुमार ने कहा कि यह पर्यटकों को एक अलग अनुभव प्रदान करेगा और ऐतिहासिक महत्ता के साथ आधुनिकता का समागम पर्यटकों को आकर्षित करेगा।

दिशा पटानी के घर के बाहर गोलीबारी : दिल्ली पुलिस ने दो नाबालिगों को हिरासत में लिया

बरेली । उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी के घर के बाहर गोलीबारी की घटना में कथित रूप से शामिल रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गिरोह के दो नाबालिग शूटर को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी के अनुसार, दोनों आरोपियों की उम्र करीब 17 वर्ष है और उन्हें दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने हिरासत में लिया है। अधिकारी के मुताबिक, दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के रहने वाले हैं और प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उनके पास से पिस्तौल और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। अधिकारी ने कहा, 'वे 11 सितंबर को अभिनेत्री के बरेली स्थित आवास के बाहर हुई गोलीबारी में सीधे तौर पर शामिल थे। वे 12 सितंबर को हुई गोलीबारी में भी शामिल थे।'

कुछ अज्ञात हमलावरों ने पटानी के बरेली स्थित आवास के बाहर 12 सितंबर को तड़के करीब पौने चार बजे कई गोलियां चलाई थीं, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी। अधिकारी ने बताया कि आगे की पूछताछ के लिए नाबालिग आरोपियों को वारंट पर बरेली भेजा जाएगा।

गोलीबारी की इस घटना में कथित रूप से शामिल रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गिरोह के दो सक्रिय सदस्य 17 सितंबर को गाजियाबाद में ट्रोनिका सिटी के पास एक मुठभेड़ में मारे गए थे। मृतकों की पहचान हरियाणा के रोहतक निवासी रविंदर और हरियाणा के सोनीपत के अरुण के रूप में हुई थी।

कुर्मी समाज की एसटी दर्जे की मांगः विधायक बोले- सरकार मानी नहीं तो आंदोलन होगा और तेज़

हज़ारीबाग़ । हज़ारीबाग़ ज़िले में कुर्मी समुदाय ने शनिवार को चरही रेलवे स्टेशन पर एक ज़ोरदार 'रेल रोको' विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिससे सुबह 8 बजे से रेल परिचालन पूरी तरह ठप हो गया। मांडू विधायक तिवारी महतो के नेतृत्व में हज़ारों पुरुष, महिलाएँ और युवा पटरियों पर बैठ गए, स्टेशन परिसर में पानी भर गया और सभी ट्रेनों की आवाजाही रोक दी। इस विरोध प्रदर्शन ने यात्रियों को अचंभित कर दिया। कई ट्रेनें अचानक रुक गईं और बढ़ती निराशा के बीच यात्री घंटों तक फंसे रहे।

रेलवे अधिकारियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और संकट से निपटने के लिए अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया है, जबकि स्थानीय प्रशासन ने स्थिति पर कड़ी नज़र रखने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किया है। प्रदर्शनकारियों ने, तैनाती से विचलित हुए बिना, समुदाय द्वारा वर्षों से झेली जा रही कथित उपेक्षा को उजागर करते हुए नारे लगाए। उनकी मुख्य माँगों में कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में शामिल करना और संविधान की आठवीं अनुसूची में कुर्माली भाषा को आधिकारिक मान्यता देना शामिल है। समुदाय के सदस्यों ने ज़ोर देकर कहा कि हमने दशकों तक भेदभाव सहा है; अब, अपनी आवाज़ उठाना कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक ज़रूरत है। एक सदस्य ने कहा, 'हमने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है, लेकिन हमें क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। हमें अच्छी नौकरियाँ नहीं मिलीं, और हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं। अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को कोटे के माध्यम से मिलने वाले लाभ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को नहीं मिलते, इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि हमारे समुदाय को एसटी का दर्जा दिया जाए।'

सभा को संबोधित करते हुए, मांडू विधायक तिवारी महतो ने राज्य और केंद्र सरकार द्वारा ठोस आश्वासन दिए जाने तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया। उन्होंने घोषणा की कि यह एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन है, लेकिन अगर हमारी जायज़ मांगों को नज़रअंदाज़ किया गया तो यह और तेज़ हो जाएगा। सरकार को निर्णायक कार्रवाई करनी होगी। यह नाकाबंदी, जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कुर्मी संगठनों द्वारा 20 सितंबर से शुरू होने वाले इसी तरह के व्यापक आंदोलन की लहर का हिस्सा है, ने क्षेत्र में हलचल मचा दी है और अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल करने के पिछले प्रयासों को विधायी मंचों पर बार-बार खारिज किया गया है, जिससे कार्रवाई की फिर से माँग उठ रही है।

लाखों भारतीयों के वीजा पर ट्रंप के फैसले के बाद एक्शन में आई मोदी सरकार, हर स्तर पर आंका जा रहा है असर

वांशिगटन। ट्रंप ने जब से अमेरिका की कमान संभाली है तब से ही वो दुनिया को परेशान करने वाले फैसले ले रहे हैं। जिसमें टैरिफ सबसे बड़ा सबूत है। टैरिफ कैसे दुनियाभर के देशों के साथ ही खुद अमेरिका को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ये अच्छे से हर किसी को पता है। यानी की ट्रंप अपनी सत्ता की सनक पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। टैरिफ के बाद अब ट्रंप ने एक और ऐसा फैसला लिया है, जिसने लाखों लोगों को परेशान कर दिया है। खासकर इसका बड़ा असर भारत पर पड़ने वाला है। दरअसल, जिस फैसले को लेकर डर बना हुआ था अब वही ट्रंप ने फैसला ले डाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एच1बी वीजा के नियम बदल दिए हैं। अब नए नियम के मुताबिक एच1बी वीजा अप्लाई करने के लिए 1 लाख डॉलर की फीस भरनी होगी।

अमेरिका द्वारा ट्रम्प द्वारा एच-1बी वीज़ा पर लगाए गए प्रतिबंधों पर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि इस कदम से परिवारों को होने वाली परेशानियों के रूप में मानवीय परिणाम होने की संभावना है। सरकार को उम्मीद है कि अमेरिकी अधिकारी इन परेशानियों का उचित समाधान कर पाएँगे। भारत ने बयान में कहा कि सरकार ने अमेरिकी एचआईबी वीज़ा कार्यक्रम पर प्रस्तावित प्रतिबंधों से संबंधित रिपोर्टें देखी हैं। इस उपाय के पूर्ण निहितार्थों का अध्ययन सभी संबंधित पक्षों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भारतीय उद्योग भी शामिल है, जिसने एचआईबी कार्यक्रम से संबंधित कुछ धारणाओं को स्पष्ट करते हुए एक प्रारंभिक विश्लेषण पहले ही प्रस्तुत कर दिया है।

भारत और अमेरिका दोनों के उद्योगों की नवाचार और रचनात्मकता में रुचि है और उनसे आगे के सर्वोत्तम मार्ग पर परामर्श की अपेक्षा की जा सकती है। कुशल प्रतिभाओं की गतिशीलता और आदान-प्रदान ने संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में प्रौद्योगिकी विकास, नवाचार, आर्थिक विकास, प्रतिस्पर्धात्मकता और धन सृजन में अत्यधिक योगदान दिया है। इसलिए, नीति निर्माता हाल के कदमों का मूल्यांकन पारस्परिक लाभों को ध्यान में रखते हुए करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच मज़बूत जन-जन संबंध शामिल हैं।

एच-1बी अब डेड हो गया

नए नियम के तहत अब एच1बी वीजा स्पांसर करने वाली कंपनियों को अब हर आवेदन के साथ एक लाख डॉलर की फीस चुकानी होगी। इस एक फैसले ने अमेरिका में काम करने की चाह रखने वाले लाखों प्रोफेसनल्स खासकर भारतीयों की उम्मीदों पर सवालिया निशान लगा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शनिवार को व्हाइट हाउस में इस ऑर्डर पर साइन किए। अब तक एच-1बी वीजा की एप्लिकेशन फीस 1 से 6 लाख रुपए तक थी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि एच-1बी का 1,00,000 डॉलर का शुल्क एक बार का शुल्क नहीं है। यह हर साल 1,00,000 डॉलर है। एच-1बी अब खत्म हो चुका है। बेहतर होगा कि इसे औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया जाए।

भारत से युद्ध की स्थिति में सऊदी अरब करेगा पाकिस्तान की रक्षा, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा दावा

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुलासा किया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए नए सुरक्षा समझौते के तहत, भारत के हमले की स्थिति में सऊदी अरब पाकिस्तान की रक्षा के लिए आगे आएगा। शुक्रवार को पाकिस्तानी समाचार चैनल जियो टीवी से बात करते हुए, आसिफ ने पुष्टि की कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ शत्रुता शुरू करता है, तो सऊदी अरब हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य होगा। आसिफ ने कहा कि हाँ, बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह समझौता किसी खास देश के खिलाफ़ नहीं है, बल्कि एक सामूहिक रक्षा समझौता है, जो दोनों देशों को किसी भी बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए बनाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई आक्रमण होता है, चाहे सऊदी अरब के खिलाफ़ हो या पाकिस्तान के खिलाफ़, हम मिलकर उसका मुक़ाबला करेंगे।

इस रक्षा समझौते की तुलना नाटो के अनुच्छेद 5 से की गई है, जो सदस्य देशों के बीच सामूहिक रक्षा पर ज़ोर देता है। आसिफ के अनुसार, यह समझौता किसी भी हमले की स्थिति में

एक-दूसरे की रक्षा करने की आपसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो नाटो के रणनीतिक ढाँचे से इसकी सीधी तुलना करता है। हालाँकि, आसिफ ने इस बात पर ज़ोर देने में सावधानी बरती कि यह समझौता पूरी तरह से रक्षात्मक है और किसी भी आक्रामक योजना का संकेत नहीं देता। आसिफ ने कहा कि यह किसी देश पर हमला करने के बारे में नहीं है। यह समझौता पूरी तरह से बाहरी खतरों के सामने रक्षा पर केंद्रित है।

नए समझौते का एक सबसे विवादास्पद पहलू पाकिस्तान की परमाणु संपत्तियों को इसमें शामिल करना है। आसिफ ने पुष्टि की कि ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान की परमाणु क्षमताएँ सऊदी अरब के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध रहेंगी। आसिफ ने कहा कि इस समझौते के तहत हमारी क्षमताएँ निश्चित रूप से उपलब्ध रहेंगी। इससे पाकिस्तान की परमाणु नीति में संभावित बदलाव का संकेत मिलता है। हालाँकि पाकिस्तान का परमाणु भंडार पारंपरिक रूप से भारत को रोकने के लिए आरक्षित रहा है, लेकिन यह समझौता आपसी रक्षा के लिए व्यापक प्रतिबद्धता का संकेत देता है।

परमाणु डील को लेकर रूस ने भारत को दिया ऐसा ऑफर, डर से पाकिस्तान ट्रंप की गोद में चढ़ जाएगा

नई दिल्ली।भारत और रूस मिलकर एक साथ कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। रूस ने अब भारत के सामने एक और प्रस्ताव पेश किया है। ये खबर सामने आई है कि रूस ने भारत के साथ सिविल परमाणु ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने के लिए बड़े और छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के स्थानीयकरण में सहयोग की पेशकश की है। ये जानकारी 19 सितंबर को सामने आई है। मौजूदा वक्त में रूस तमिलनाडु के कुंडककुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण कर रहा है। रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसटोम के मुताबिक इसके महानिदेशक एलेक्सी लिकाचेव ने 15-20 सितंबर को वियना में आयोजित अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की 69वीं वार्षिक सभा के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात में ये प्रस्ताव सामने रखा है। रोसाटॉम के एक बयान के मुताबिक भारत के साथ बाततीच रोसाटॉम के एक रणनीतिक साझेदार हैं, उनकी शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित की गई। रोसाटॉम ने भारत की मजबूत औद्योगिक क्षमताओं को और ज्यादा ताकत देने के लिए बड़े और छोटे पैमाने के परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजनाओं के स्थानीयकरण की पेशकश की है।

यूरोप के कई हवाई अड्डों पर बड़ा साइबर हमला, यात्री हो रहे परेशान

नई दिल्ली। चेक-इन और बोर्डिंग सिस्टम के लिए ज़िम्मेदार सेवा प्रदाता को निशाना बनाकर किए गए एक साइबर हमले ने ब्रुसेल्स हवाई अड्डा, लंदन हीथ्रो और बर्लिन ब्रैंडेनबर्ग हवाई अड्डे जैसे कई प्रमुख यूरोपीय हवाई अड्डों पर भारी व्यवधान पैदा कर दिया है। शुक्रवार देर रात हुए इस हमले के कारण हवाई अड्डों को मैन्युअल चेक-इन और बोर्डिंग प्रक्रिया अपनानी पड़ी, जिसके कारण उड़ानों में काफ़ी देरी हुई और उड़ानें रद्द हुईं। ब्रुसेल्स हवाई अड्डे पर कई उड़ानें रद्द कर दी गईं और यात्रियों को सलाह दी गई कि वे केवल तभी यात्रा करें जब उनकी उड़ानें कन्फर्म हों। उन्होंने यात्रियों से शेंगेन उड़ानों से दो घंटे पहले और गैर-शेंगेन उड़ानों से तीन घंटे पहले पहुँचने का आग्रह किया ताकि धीमी मैन्युअल प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके। लंदन हीथ्रो ने भी तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाता द्वारा उत्पन्न तकनीकी समस्या के कारण देरी की चेतावनी दी। हालाँकि प्रभावित हवाई अड्डों की पूरी सूची अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन व्यवधान व्यापक था।

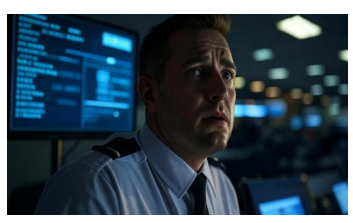

हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रभावित सेवा प्रदाता कोलिन्स एयरोस्पेस है, जो चेक-इन और बोर्डिंग सिस्टम का एक प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता है। कंपनी सेवाओं को बहाल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। ब्रुसेल्स हवाई अड्डे ने हुई असुविधा पर खेद व्यक्त किया और यात्रियों को आश्वस्त किया कि समस्या के समाधान के प्रयास जारी हैं।

अप्रभावित हवाई अड्डे

ज़्यूरिख हवाई अड्डे और फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे ने बताया कि उनके सिस्टम साइबर हमले से अप्रभावित रहे और सामान्य रूप से परिचालन जारी रहा।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 Twitter: https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 Mobile No: 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित । कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी
E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/ इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)